राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस
क्रांति समय दैनिक समाचार में प्रेसनोट,नोटिस,वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उत्तरांचल,उत्तराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

सुरत-गुजरात,संस्करण बुधवार,27 अक्टूबर-2021 वर्ष-4,अंक-276 पृष्ठ-08 मूल्य-01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सूरत की पीपलोद पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिस के परिजन थाली लेकर सड़क पर उतर आए

क्रांति समय ,सूरत

सूरत गुजरात पुलिस ग्रेड वेतन वृद्धि आंदोलन का मामला धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। राजनीतिक दलों समेत सामाजिक संगठनों के आगे आने पर पुलिस परिवार के सदस्य भी विरोध में उतर आए हैं. सूरत पीपुल्स पुलिस लाइन में रहने वाला एक पुलिस परिवार थाली लेकर सड़क पर उतर आया है. गृह मंत्री के शहर में विरोध प्रदर्शन भी चर्चा का विषय बन गया है। महिलाओं के विरोध में सड़कों पर उतरने के बाद राजनीतिक बवाल मच गया है। इस समय यह आंदोलन पूरे गुजरात में चल

रहा है। पुलिस कर्मियों के साथ परिवार भी विरोध में शामिल हो गया।गुजरात पुलिस ग्रेड-पे के मुद्दे पर एक सप्ताह से अधिक समय से आंदोलन कर रही है। आम आदमी पार्टी, युवा कांग्रेस और करणीसेना भी पुलिस के समर्थन में उतर आए हैं। गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत और राजकोट में कई संगठन पुलिस के समर्थन में आगे आ रहे हैं. प्रदर्शन में पुलिसकर्मी के साथ उनका परिवार भी शामिल हो रहा है.

क्या है पुलिस कर्मियों की मांग गुजरात के विभिन्न कर्मचारी संघों के दबाव के चलते कर्मचारियों के ग्रेड पे और भत्तों में सुधार किया जा रहा है. राज्य के सभी कर्मचारियों को मिलने वाले लाभों के संबंध में संवैधानिक समानता बनाए रखने के लिए पुलिस कर्मियों के जनहित में कर्मचारियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की मांग की गई है। राज्य के एएसआई (सहायक उप निरीक्षक), हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल का ग्रेड पे बहुत कम है। इसके बजाय, गुजरात पुलिस के सभी कर्मियों के वृद्धावस्था भत्ते में 4200, 3600, 2800 ग्रेड देने के साथ-साथ तत्काल वृद्धि की मांग की गई है। ये पुलिस कर्मियों के साथ-साथ यूनियन बनाने से ग्रेड पे बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। साथ ही पुलिस कर्मियों को 20 रूपये साइकिल भत्ता दिया जाता है।

डीईओ ने नियमों का उल्लंघन करने पर शहर के छह सहित 15 स्कूलों की मान्यता रद्द की

क्रांति समय ,सूरत

राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा शिक्षा विभाग के नियमों के खिलाफ काम करने वाले और बीयूसी नहीं होने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश के बाद शहर के छह सहित कुल 15 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है। जिले भर के 15 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी गई है, जिनमें 6 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास बीयू सर्टिफिकेट नहीं है और शिक्षा अधिकारी को कोई जानकारी नहीं दी है. इनमें अमरोली, कटारगाम, वराछा, डिंडोली और लिंबायत के स्कूल शामिल हैं। ऐसे स्कूलों की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी एचएच राज्यगुरु ने शिक्षा निदेशक को भेजी थी। तब से मान्यता की कार्यवाही शुरूकी गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी ने संस्कार ज्योति, बालभारती, तक्षशिला, सरदार स्कूल, तिलक विद्यालय, ज्ञान ज्योति स्कूल समेत जिले के कुल 15 स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी है. निदेशक ने एक आदेश में कहा कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अन्य स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा।

ऐसे में यह सुनिश्चित करना शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी है कि किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित न किया जाए। बच्चों के शिफ्टिंग की रिपोर्ट शिक्षा निदेशक को भेजनी होगी।

ग्रेड पे की मांग को लेकर गुजरात पुलिसकर्मियों ने शुरूकिया आंदोलन

क्रांति समय ,सूरत

गुजरात पुलिस के जवानों ने ग्रेड बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर आंदोलन चल रहा था, अब सड़कों पर उतर आया है। ग्रेड पे को लेकर पुलिसकर्मी समेत उनका परिवार भी आंदोलन में शामिल हो गया है। आज गांधीनगर में सेवारत पुलिसकर्मियों ने बगैर यूनिफार्म अपने परिवार के साथ सत्याग्रह छावनी में डेरा जमा लिया है। पुलिस के इस आंदोलन को राजनीतिक और सामाजिक समर्थन भी मिल रहा है। बीती रात गांधीनगर के सेक्टर 28 स्थित एलसीबी कचहरी में 600 जितने पुलिसकर्मी ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर एकत्र हुए थे। उनके समर्थन में गुजरात विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष परेश धानाणी भी पहुंच गए। आंदोलनकारियों के बीच पहुंचे परेश धानाणी ने कहा कि ग्रेड पेड बढ़ाने की उनकी मांग का समर्थन करते हैं। पुलिसकर्मियों का ग्रेड पे बढ़ाने के बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल को पत्र भी लिखा है। जिसमें मुख्यमंत्री से गुजरात में एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल का ग्रेड पे काफी कम है। जिसमें तत्काल वृद्धि की जानी चाहिए। साथ ही राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की सेवा का समय तय किया जाए और 8 घंटे से अधिक सेवा के एवज में मुआवजा दिया जाना चाहिए। ऋतुओं को ध्यान में रखते हुए पुलिसकर्मियों को जरूरी सुरक्षा साधन उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा राज्य के पुलिसकर्मियों को यूनियन बनाने का मूलभूत अधिकार तुरंत दिया जाना चाहिए। गौरतलब है कि पुलिसकर्मियों की छुट्टी, ग्रेड पे और सेवा के समय को लेकर लंबे समय से पेशकश की जा रही है। ग्रेड पे को लेकर पुलिस विभाग में शुरूहुई हलचल बड़ा आंदोलन का रूप लेगी या नहीं, यह तो आनेवाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज गांधीनगर में पुलिसकर्मियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है और उनका परिवार हौशला बढ़ा रहा है।

तेज रफ्तार से होनेवाली दुर्घटनाएं रोकथाम के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम

क्रांति समय ,सूरत

गुजरात सरकार ने राज्य में तेज रफ्तार की वजह से होनेवाली दुर्घटनाओं की रोकथाम और दुर्घटना के बाद घायलों को त्वरित उपचार मुहैया कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 48 इंटरसेप्टर और 42 फर्स्ट रिपोन्स व्हीकल तथा रेस्क्यु व्हीकल राज्य पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। मंगलवार को गांधीनगर में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखार रवाना किया। वाहनों का प्रस्थान कराते हुए हर्ष संघवी ने कहा कि ऑवर स्पीड के कारण होनेवाली दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से अत्याधुनिक साधनों से लैस रडार स्पीड गन के साथ इन्टरसेप्टर वैन तैयार की गई है। ऐसी 48 वैन आज विभिन्न जिलों को सौंपी गई है। साथ ही दुर्घटना के दौरान वाहन में फंसे घायलों को निकालने में मदद मिले इसके लिए 42 हाईवे पेट्रोल वाहन भी राज्य के विभिन्न शहर और जिलों का उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में पुलिस विभाग और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से विभिन्न सुविधायुक्त 1100 जितने टूव्हीलर और अन्य वाहनों की जरूरत के मुताबिक खरीदी की जाएगी। आपको बता दें कि गुजरात

पुलिस को उपलब्ध कराई गई 48 इन्टरसेप्टर वैन की डिजाइनिंग में हाईक्वॉलिटी की रिफ्लेक्टिव सेफ्टी स्ट्रीप्स और साइनेज समेत गुजरात पुलिस के लोगो के साथ तैयार की गई है। सरकार की ओर से उपलब्ध कराई गई वैन में अत्याधुनिक लेसर स्पीड गन, पीटीझेड कैमरा, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, मोबाइल नेटवर्क वीडियो रिकार्डर, अग्निशामक एवं फर्स्ट एइड बोक्स इत्यादि उपलब्ध है। इस वैन द्वारा ऑवर स्पीड वाहनों पर नियंत्रण किया जाएगा। इंटरसेप्टर वैन इनोवा में तैयार की गई है और इनकी कीमत रु 10.46 करोड़ है। अहमदाबाद शहर को 4, सूरत शहर को 3, राजकोट शहर को 2 वडोदरा शहर को 2 और जिलों में 1-1 समेत कुल 48 इन्टरसेप्टर वाहनों का आवंटनकिया गया है। हाईवे पेट्रोल वाहन शहर और जिला स्थित मुख्य राजमार्ग पर पेट्रोलिंग कर दुर्घटना के दौरान फर्स्ट रिपोन्स व्हीकल और रेस्क्यू व्हीकल के तौर पर काम करेंगे। इस वाहन के जरिए दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बहार निकालने और अस्पताल पहुंचाया जाएगा। राज्यभर में शहर और जिला यूनिट को एक-एक समेत कुल 42 हाईवे पेट्रोल वाहन आवंटित किए गए हैं। 42 हाईवे पेट्रोल वाहन कुल रु 6.56 करोड़ से अधिक लागत से तैयार किए गए हैं। हाईवे पेट्रोल वाहन में हाइड्रोलीक रेस्क्यू किट, स्ट्रेचर, पोर्टेबल इमर्जंसी लाइट बैग, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ स्टील रस्सी, हाइड्रोलिक जेक, वुड कटर, माइक और सायरल के साथ रूफ लाइट बार और पीए सिस्टम, पीटीझेट कैमरा, डे-नाइट, अग्निशामक, रिचार्जेबल टोर्च, फर्स्ट एइड बोक्स, एलईडी मोनिटर, मोबाइल नेटवर्क वीडियो रिकार्ड और रिअर कैमरे जैसी सुविधाओं से लैस है।

गुजरात में ग्रेड पे सिस्टम नहीं, 7वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन व्यवस्था : ब्रिजेश झा

क्रांति समय ,सूरत

पुलिसकर्मियों के ग्रेड पे बढ़ाने के मुद्दे पर चल रहे आंदोलन के बीच आईपीएस ब्रिजेश झा ने स्पष्ट किया है कि गुजरात में ग्रेड पे सिस्टम नहीं है। राज्य में सातवें वेतन आयोग के मुताबिक पुलिसकर्मियों को वेतन दिया जाता है। ग्रेड पे मुद्दे को लेकर शुरु हुए आंदोलन के संदर्भ में मंगलवार को गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के बीच बैठक हुई। जिसमें पुलिसकर्मियों के वेतन और उन्हें दी जानेवाली सुविधा समेत उनकी समस्याओं के बारे में गृह राज्यमंत्री को अवगत कराया गया। साथ ही अन्य राज्य के ग्रेड पे के मुद्दों पर बैठक में चर्चा की गई। बैठक के बाद आईपीएस अधिकारी ब्रिजेश झा ने पत्रकार परिषद में स्पष्ट किया कि देश के किसी भी राज्य में 4200 ग्रेड पे पुलिसकर्मियों को दिया जाता होने का कोई प्रमाण नहीं है। हर राज्यों से इस संदर्भ में ब्यौरा मंगवाया गया है

कार्यालय ऑफिस
क्रांति समय दैनिक समाचार में प्रेसनोट,नोटिस,वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-krantisamay@gmail.com

समस्या आपकी हमें भेजे
अपने क्षेत्र में समस्याएं हमें लिखे या बताएँ और समस्याएं का हल संबंधित विभाग से मिलेगा
मोबाईल:-987914180
या फोटा,वीडियो हमें भेजे

कार्यालय ऑफिस
क्रांति समय दैनिक समाचार
भारत के अन्य राज्यों में जिला ब्यूरों और अन्य शहर,ग्राम में पत्रकारों की नियुक्त के लिए आवेदन कर सकते है
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-krantisamay@gmail.com

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

चिकित्सा सेवा विस्तार

अपने देश में चिकित्सा सेवा का विस्तार सुखद और स्वागतयोग्य है। इसमें भी जब उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में नौ मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है, तो खुशी दोगुनी हो जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 2,329 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित इन मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया है, जो सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और जौनपुर जिलों में स्थित हैं। कॉलेजों का उद्घाटन करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, 'नौ मेडिकल कॉलेज स्वस्थ भारत के सपनों को साकार करेंगे। ये राज्य के लोगों के लिए एक उपहार हैं।' वाकई इन मेडिकल कॉलेज के खुलने से उत्तर प्रदेश में अस्पताल सुविधा में लगभग 2,500 बिस्तर जुड़ जाएंगे। गौर करने की बात है कि ये ज्यादातर मेडिकल कॉलेज पूर्वांचल में स्थित हैं, जहां चिकित्सा का ढांचा अपेक्षाकृत रूप से कमजोर है। कोरोना के समय भी हमने इन इलाकों में चिकित्सकीय जरूरतों को महसूस किया है। निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, लेकिन उससे आम समाज की जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में न केवल चिकित्सा की पढ़ाई, बल्कि चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सकों की संख्या का बढ़ना अनिवार्य है। जुलाई महीने तक देश में 558 मेडिकल कॉलेज सेवाएं दे रहे थे, जिनमें से 289 सरकारी और 269 गैर-सरकारी थे। अलग-अलग चरण में नरेंद्र मोदी सरकार के समय करीब 157 मेडिकल कॉलेज खुले हैं या उन्हें मंजूरी मिली है। आंकड़ों से साफ है कि निजी मेडिकल कॉलेज की संख्या ज्यादा है, सरकारी मेडिकल कॉलेज की संख्या निजी कॉलेजों से बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज न सिर्फ किफायती दर पर चिकित्सक तैयार करते हैं, बहुत किफायती दर पर चिकित्सा सेवा भी देते हैं। इसके अलावा निजी मेडिकल कॉलेज से पैसे खर्च करके डिग्री हासिल करने वाले चिकित्सकों पर कमाने का दबाव भी ज्यादा रहता है। सरकारी मेडिकल कॉलेज की ज्यादा संख्या किसी भी राज्य के सामाजिक विकास के लिए बेहतर संकेतक हो सकती है। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार हर जिले में एक-एक मेडिकल कॉलेज खोलने के सपने के साथ आगे बढ़ रही है, तो स्वागत है। बेशक, विगत वर्षों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में प्रगति हुई है, लेकिन इस काम में और तेजी लाने की जरूरत है। यह भी किसी खुशखबरी से कम नहीं कि सोमवार को प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का भी शुभारंभ किया है। दावा है कि स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए यह देश की सबसे बड़ी योजना है। चिकित्सा क्षेत्र में अभी भारत को बहुत लंबा सफर तय करना है। डॉक्टर और मरीज अनुपात के अलावा चिकित्सा की आधारभूत सेवाओं का बड़ा अभाव है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की कमियों पर भी गौर करना चाहिए। सरकार की इस योजना की विदेश में भी तारीफ हुई है, लेकिन यह देखना भी जरूरी है कि निजी अस्पताल क्या आम गरीब मरीजों को पूरा लाभ दे रहे हैं? क्या महामारी के समय अब इन अस्पतालों से कोई भी निराश नहीं लौटेगा? किसी भी विकास को जमीनी स्तर पर जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकारों को पूरी मुस्तैदी से सेवाओं की निगरानी करनी पड़ेगी।

'आज के ट्वीट

विश्वास

अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो सम्भव है तो आपको शक्ति की ज़रूरत होती है, पर जब आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो असम्भव है तो आपको विश्वास की ज़रूरत होती है.

-- रजत शर्मा

ऊंचे तेल दामों से आर्थिकी को मजबूती भी

भरत झुनझुनवाला

वर्ष 2016 की तुलना में आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम 3 गुना हो गए हैं। इसी के समानांतर अपने देश में पेट्रोल का दाम लगभग 70 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 100 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इसका सीधा प्रभाव महंगाई पर पड़ता है। हमारे लिए यह मूल्य वृद्धि विशेषकर कष्टप्रद है क्योंकि हम अपनी खपत का 85 प्रतिशत तेल आयात करते हैं। अत: यदि किसी प्राकृतिक आपदा अथवा युद्ध जैसी स्थिति में तेल का आयात नहीं हो सका तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो जाएगी। इसलिए प्रधानमंत्री ने सही कहा था कि हमें अपनी तेल की खपत में आयात का हिस्सा घटाकर 50 प्रतिशत पर लाना चाहिए। तेल की मूल्य वृद्धि से हम इस दिशा में बढ़ेंगे क्योंकि महंगे तेल से तेल की खपत कम होगी। फिर भी तेल के ऊंचे मूल्य की तीन प्रमुख हानियां हैं, जिन पर गौर करना होगा। पहली हानि यह कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ता है। तेल महंगा होता है तो हमें उसके आयात के लिए अधिक मात्रा में डॉलर से पेमेंट करना पड़ता है। डॉलर को अर्जित करने के लिए हमें अधिक मात्रा में अपना माल निर्यात करना पड़ता है। अधिक मात्रा में माल को निर्यात करने के लिए हमें अपने माल के दाम को अक्सर घटाना पड़ता है। जैसे बच्चे का विवाह करना हो तो परिवार अपनी भूमि को औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर हो जाता है। इसलिए तेल के ऊंचे दाम से हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है। लेकिन इसका उपाय उपलब्ध है। यदि हम विनिर्माण के स्थान पर सेवा क्षेत्र पर ध्यान दें तो हम उतनी ही ऊर्जा से अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। सिनेमा, संगीत, मेडिकल, ट्रांसक्रिप्शन, विभिन्न भाषाओं में अनुवाद इत्यादि कार्य में ऊर्जा का उपयोग कम होता है। विनिर्माण की तुलना में सेवा क्षेत्र में दसवां हिस्सा ऊर्जा लगती है। हमें इस दिशा में इंग्लैंड से सबक लेना चाहिए। इंग्लैंड द्वारा सेवा क्षेत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता है। इंग्लैंड की आय में वित्तीय सेवाओं, पर्यटन और शिक्षा सेवाओं का भारी योगदान है। इस कारण 1 लीटर तेल में इंग्लैंड 16.2 डॉलर की आय अर्जित करता है। चीन द्वारा विनिर्माण अधिक किया जाता है, इसलिए चीन उसी 1 लीटर तेल में केवल 5.3 डॉलर की आय अर्जित करता है। भारत इन दोनों देशों के बीच में है। हम 1 लीटर तेल से 8.2 डॉलर की आय अर्जित करते हैं। अत: यदि हम इंग्लैंड की तरह वित्तीय, पर्यटन और शिक्षा सेवाओं का विस्तार करें तो हम वर्तमान में जो तेल की खपत हो रही है, उसी से दोगुना आय अर्जित कर सकते हैं। यद्यपि यह सही है कि तेल के ऊंचे दाम से हमारा व्यापार घाटा बढ़ता है लेकिन इसकी काट उपलब्ध है। तेल के ऊंचे दाम का दूसरा प्रभाव महंगाई पर पड़ता है। 2018 में अपने देश में महंगाई की दर 3.4 प्रतिशत थी जो आज बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई है। लेकिन साथ-साथ जीएसटी की वसूली में भी सुधार हुआ है। 2018 में हम प्रतिमाह लगभग 90 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी वसूल कर रहे थे जो कि सितंबर, 2021 में बढ़कर 117 हजार करोड़ हो गया है। अर्थ हुआ कि अपने देश में आर्थिक गतिविधियां तीव्र गति से चल रही हैं, जिसके कारण महंगाई में वृद्धि हो रही है, जिस प्रकार बाइक को तेज चलाने से वह गर्म हो जाती है। अत: महंगाई को केवल तेल पर आरोपित करना उचित नहीं है। इसका मूल कारण अर्थव्यवस्था की गति दिख रही है। तेल का महंगाई पर यूं भी प्रभाव न्यून है। एक अध्ययन के अनुसार पेट्रोल के दाम में 100 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि होती है तो उसका महंगाई पर 1 प्रतिशत प्रभाव पड़ता है। डीजल के दाम में 100 प्रतिशत की वृद्धि होती है तो उसका महंगाई पर 2.5 प्रतिशत का प्रभाव पड़ता है। दोनों का सम्मिलित प्रभाव 1.5 प्रतिशत मान सकते हैं। तेल के दाम में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इसलिए इसका महंगाई पर प्रभाव मात्र 0.8 प्रतिशत माना जा सकता है। इसलिए वर्तमान में जो महंगाई बढ़ी है, उसमें तेल का हिस्सा कम है और जो आर्थिक गति में तीव्रता आई है, उसका हिस्सा ज्यादा दिख रहा है। यद्यपि यह सही है कि तेल का महंगाई पर प्रभाव पड़ता है लेकिन इसको महंगाई का प्रमुख कारण नहीं बताया जा सकता। तीसरा तर्क है कि तेल की मूल्य वृद्धि से वित्तीय घाटा बढ़ता है। यह तर्क पूर्णतया भ्रामक है। वर्तमान में अपने देश में आयातित तेल पर 36 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार द्वारा वसूल की जाती है। यदि आयातित पेट्रोल का दाम 50 रुपये प्रति लीटर हो तो उस पर 18 रुपये की एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाएगी। यदि इसी आयातित पेट्रोल का दाम 70 रुपये प्रति लीटर हो जाये तो उस पर 25 रुपये की एक्साइज ड्यूटी वसूल की जाएगी। तेल के दाम में वृद्धि के साथ-साथ एक्साइज ड्यूटी की वसूली भी बढ़ती है, इससे सरकार को राजस्व अधिक मिलता है और वित्तीय घाटा कम होता है, न कि बढ़ता है। हां इतना जरूर है कि यदि तेल के बढ़ते मूल्य पर नियंत्रण करने के लिए सरकार एक्साइज ड्यूटी में कटौती करे तो सरकार का राजस्व घटेगा; परंतु तब वह प्रभाव तेल के दाम में वृद्धि का नहीं बल्कि एक्साइज ड्यूटी में कटौती का कहा जाएगा। इन प्रभावों के सामने तेल के ऊंचे मूल्य के कई लाभ हैं। पहला यह कि तेल के मूल्य विश्व अर्थव्यवस्था की गति को दर्शा रहे हैं। विश्व अर्थव्यवस्था की इस गति के कारण हमारे निर्यात बढ़ेंगे और हमारे प्रवासियों द्वारा जो रेमिटेंस भेजी जाती है, उसमें भी वृद्धि होगी। दूसरा सुप्रभाव यह कि जब तेल महंगा होता है तो हम ऊर्जा उपयोग की कुशलता में सुधार करते हैं। जैसे यदि तेल महंगा होता है तो बाइक खरीदते समय हम ध्यान रखते हैं कि वह कितना एवरेज देती है। यदि तेल सस्ता होता है तो हम एक्सलेरेशन अथवा अन्य बातों पर ध्यान अधिक देते हैं और एवरेज पर कम। अत: तेल के ऊंचे दाम से हमारी ऊर्जा के उपयोग की कुशलता बढ़ती है। तीसरा लाभ यह है कि तेल के ऊंचे दाम से तेल की खपत कम होने से ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, जिससे बाढ़, सूखा, तूफान इत्यादि प्राकृतिक आपदाएं कम होंगी और हमारी अर्थव्यवस्था कम प्रभावित होगी। चौथा लाभ यह कि तेल के ऊंचे दाम के समानांतर देश में ऊर्जा का दाम ऊंचा होगा तो सौर और वायु ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। अत: तेल के ऊंचे मूल्य का समग्र आकलन करें तो हानि को हम काट सकते हैं जबकि लाभ को हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। तेल के ऊंचे दाम का स्वागत करना चाहिए।

लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं।

जीवन-मृत्यु

जग्गी वासुदेव

जब हम किसी प्रियजन को खोते हैं, चाहे उनकी बीमारी या मृत्यु हो जाए या वे छोड़ कर चले जाएं-चाहे हम किसी भी वजह से उन्हें खोएं, सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि हमारे जीवन में उनकी जो जगह थी, उसके कारण वे एक खालीपन छोड़ जाते हैं। हमें समझना चाहिए कि जीवन की प्रकृति ही ऐसी है कि आपको और आपके प्रियजनों को कभी न कभी मृत्यु का शिकार होना ही है। बात बस यह है कि किसकी मृत्यु पहले होगी। अगर हमारे आसपास के लोगों ने हमारे जीवन को बेहतर बनाया है, और हम उन्हें याद करते हैं, तो हमें उन्हें खुशी के साथ याद करना चाहिए। उनकी रवानगी को दुखद नहीं बनाना चाहिए। उनकी यादों को आपके लिए खुशी और प्रेम के आंसू लेकर आना चाहिए, पीड़ा के नहीं। मैं समझता हूं कि आपके मृत प्रियजन आपके लिए क्या मायने रखते थे। मगर मैं चाहता हूं कि आप उन्हें सभी अच्छी बातों के लिए याद करें। अगर आप उनसे पहले मर जाते, तो आप उन्हें एक बुरी जगह छोड़ जाते, इसलिए कृपया एक इंसान के रूप में अपना आत्मविश्वास बटोरें। अगर आपके मृत प्रियजन ने आपके लिए बहुत सी अच्छी चीजें कीं, तो कृपया वही चीजें आप उन लोगों के लिए कीजिए, जो अब भी आपके आसपास हैं। जीवन ऐसे ही आगे बढ़ता है। जब मैं 'जीवन' कहता हूं, तो मैं असली जीवन की बात कर रहा होता हूं, न कि आपके कामों के बारे में। अधिकांश लोगों को लगता है कि जीवन उन चीजों का एक कोलाज है, जिन्हें उन्होंने इकट्ठा किया है। जब उस कोलाज का एक टुकड़ा गिर जाता है, तो अचानक आपको लगता है मानो जीवन खत्म हो गया है, जो कि सच नहीं है। आपके जीवन में कुछ लोगों के आने से पहले भी आप जीवित थे, हंसते थे, खुश होते थे। आपने लोगों को अपने जीवन में यह सोच कर जोड़ा कि इससे आपका जीवन समृद्ध होगा या शायद कोई जरूरत पूरी करनी थी। वह सब ठीक है, मगर अब पहचान जोड़ लेने के कारण किसी खास इंसान के चले जाने पर आपको लगता है कि जीवन का एक टुकड़ा चला गया है।

आज का राशिफल

मेष	पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। आपके वर्चस्व तथा प्रभाव में वृद्धि होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे।
वृषभ	जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। रुके हुए कार्य सम्पन्न होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। नए अनुबन्ध प्राप्त होंगे।
मिथुन	प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। आर्थिक लाभ होगा। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा।
कर्क	पारिवारिक जनों के मध्य सुखद समाचार मिलेगा। रोजी रोजगार के प्रयास सफल होंगे। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
सिंह	व्यावसायिक योजना सफल होगी। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। वाणी की सौम्यता से रुके हुए कार्य सम्पन्न होंगे। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। नए अनुबन्ध प्राप्त होंगे।
कन्या	जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। आय के नए स्त्रोत बनेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे।
तुला	पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है।
वृश्चिक	आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। व्यावसायिक दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। विरोधियों का पराभव होगा। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।
धनु	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। किया गया परिश्रम सार्थक होगा। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।
मकर	राजनैतिक दिशा में किए गए प्रयास फलीभूत होंगे। व्यावसायिक व पारिवारिक समस्याएं रहेंगी। आर्थिक संकट से गुजरना होगा। वाणी की सौम्यता आपको सम्मान दिलायेगी।
कुम्भ	बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। टकराव की स्थिति आपके लिए हितकर नहीं होगी। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन आगमन होगा। कुटुम्बजनों का सहयोग मिलेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।
मीन	कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। भारी व्यय का सामना करना पड़ेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय के नवीन स्त्रोत बनेंगे।

खत्म हो तारीख-पे-तारीख का भय

अनूप भटनागर

हमारी न्यायपालिका भले ही नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों और कार्यपालिका की कार्रवाई के खिलाफ उनकी वैयक्तिक स्वतंत्रता और हितों की रक्षा के बारे में बार-बार आश्वासन देती है लेकिन इसके बावजूद आज भी आम नागरिक अदालत के नाम से डरता है। आम नागरिकों में एक धारणा गहरे तक पैठ किये है कि एक बार विवाद अदालत में पहुंचा तो न्याय कब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि त्वरित व सस्ता तथा सुगम न्याय प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं। त्वरित और सुगमता से न्याय दिलाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि देश में न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही बेहतर सुविधाओं के साथ अदालती कक्षों की संख्या भी बढ़ाई जाए। यह भी सुनिश्चित हो कि अनावश्यक रूप से मुकदमों की सुनवाई स्थगित नहीं हो। नागरिकों के मन में जल्दी न्याय नहीं मिलने की आशंका तेजी से घर कर रही है। इसकी वजह दीवानी और फौजदारी मुकदमों का सालों तक लंबित रहना भी है। एक साधारण व्यक्ति के मन में अदालत में 'तारीख पे तारीख' की दहशत है। त्वरित न्याय नहीं मिलने की एक बानगी हाल में उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज की गयी एक याचिका है। इस मामले में पश्चिम बंगाल की एक महिला द्वारा 1971 में 3000 हजार रुपये की वसूली के लिए दायर मुकदमा करीब 50 साल चला। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे 'कभी न थकने वाला विक्रमादित्य' बताया। रमा देवी नाम की इस महिला ने 1974 में मुकदमा जीत लिया था लेकिन इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अक्तूबर में खत्म किया है। साथ ही न्यायालय ने इस प्रकरण को कानून के छात्रों के लिए विधि पाठ्यक्रम में भी शामिल करने का सुझाव दिया है। इस तरह के कई उदाहरण मौजूद हैं, जिसमें वादकारी आम नागरिक को न्याय मिलने में 20 साल से लेकर 45 साल का वक्त लगा। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण भी इस तथ्य से अवगत हैं और यही वजह है कि उन्होंने पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम में इस बात पर जोर भी दिया कि आम आदमी को अदालतों में आने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका के प्रति जनता की आस्था लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। निःसंदेह न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड के आंकड़ों पर नजर डालें तो वह खुद ही आम नागरिक के मन की शंका बयां करती है। मसलन, राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार इस समय देश की अदालतों में कम से कम 32,57, 580 मुकदमे दस साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। इनमें आपराधिक मामलों की संख्या 25,63,616 और दीवानी मामलों की संख्या 6,93,964 है। इन आंकड़ों में 36,214 दीवानी मुकदमे और 63,509 आपराधिक मुकदमे 30 साल से भी ज्यादा समय से न्याय की बाट जोह रहे हैं। इनमें से अनेक वादकारियों या प्रतिवादियों का अब तक शायद निधन भी हो गया होगा। इसी प्रकार 20 साल से ज्यादा समय से लंबित दीवानी मामलों की संख्या भी 1,13,998 और आपराधिक मुकदमों की संख्या 3,61,714 है। यही नहीं, उच्चतम न्यायालय में पांच, सात और नौ सदस्यीय संविधान पीठ के विचारार्थ भी इस समय 421 मामले लंबित हैं। इनमें नौ सदस्यीय संविधान पीठ के 135 और सात सदस्यीय संविधान पीठ के विचारार्थ 15 मामले हैं जबकि पांच सदस्यीय संविधान पीठ के विचारार्थ 271 मुकदमे लंबित हैं। इस तरह के डराने वाले आंकड़ों के मद्देनजर कोई भी आम आदमी अपने किसी विवाद के लिये अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले दस बार सोचता है कि इसके समाधान के लिये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना कितना उचित होगा। इस स्थिति के लिए काफी हद तक कार्यपालिका भी जिम्मेदार है जो मुकदमों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियां नहीं करती और अदालती कक्षों के निर्माण का सवाल उठने पर पैसे का रोना रोने लगती है। प्रधान न्यायाधीश ने अपने हालिया भाषण में इस तथ्य को इंगित करते हुए कहा है कि देश में न्यायिक अधिकारियों की कुल संख्या 24, 280 और किराये के 623 परिसरों सहित अदालती कक्षों की संख्या 20,140 है। उन्होंने यह भी कहा कि देश में अदालतों के लिए बेहतर न्यायिक सुविधाओं के बारे में सबसे अंत में सोचा जाता है। न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि न्याय प्रदान करने की प्रभावी व्यवस्था के लिए न्यायपालिका को बेहतर बनाना जरूरी है क्योंकि प्रभावशाली न्यायपालिका अर्थव्यवस्था के विकास में मददगार हो सकती है जबकि न्याय प्रदान करने में विफलता देश को प्रभावित करती है। विवादों के शीघ्र समाधान में लोक अदालतें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नियमित रूप से लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद करोड़ों लंबित मुकदमे अभी भी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। जिला स्तर पर मुकदमों का निपटारा तभी संभव हो सकेगा जब राज्य स्तर पर न्यायपालिका के मुखिया अर्थात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निचली अदालतों में लंबित मुकदमों की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने और अनावश्यक कारणों से सुनवाई के स्थगन पर अंकुश लगाने के लिए ठोस दिशा निर्देश बनायें।

गडकरी ने हरित हाइड्रोजन की वकालत की, तेल आयात घटाने को कहा

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने परिवहन ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन की वकालत करते हुए आयात पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया है। गडकरी ने सोमवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को एक ऐसा देश बनाने की जरूरत है जो पेट्रोल और डीजल के आयात पर निर्भर नहीं हो। उन्होंने इस बात पर क्षोभ जताया कि कई देश पेट्रोल और डीजल की बिक्री के धन का इस्तेमाल आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए कर रहे हैं। मंत्री ने कहा, ''हरित हाइड्रोजन पेट्रोल और डीजल से बेहतर है। परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ रहा है।'' उन्होंने कहा, ''हम भारत को ऐसा देश बनाना चाहते हैं, जो पेट्रोल और डीजल के आयात पर निर्भर नहीं हो, बल्कि ईंधन का निर्यात करे।'' उन्होंने कहा कि यह एक राष्ट्रवादी विचार है। गडकरी ने कहा, ''पेट्रोल और डीजल का आयात कर हम उन देशों को अमीर कर रहे हैं जो आतंकवाद का वित्त पोषण करते हैं।'' हालांकि, उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल का आयात घटाकर देश कई समस्याओं को हल कर सकता है।

फेसबुक का मुनाफा 17फीसदी बढ़ा

अमेरिका: सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने बताया कि जूलाई-सितंबर 2021 तिमाही के दौरान उसकी शुद्ध आय 17 फीसदी बढ़कर 9.19 अरब अमेरिकी डॉलर या 3.22 डॉलर प्रति शेयर हो गई। कंपनी को एक साल पहले की समान अवधि में 7.85 अरब अमेरिकी डॉलर या 2.71 डॉलर प्रति शेयर का मुनाफा हुआ था। समीक्षाधीन अवधि में फेसबुक की आय 35 प्रतिशत बढ़कर 29.01 अरब डॉलर हो गई। इस दौरान उसकी विज्ञापन आय में मजबूत बढ़ोतरी हुई। फैक्टसेट के एक सर्वेक्षण के अनुसार विश्लेषकों को औसतन 24.49 अरब अमेरिकी डॉलर की आय के साथ प्रति शेयर 3.19 अमेरिकी डॉलर के मुनाफे की उम्मीद थी।

लगातार दूसरे दिन नहीं बदली तेल की कीमत, दिल्ली में 107 के पार पहुंचा पेट्रोल

बिजनेस डेस्क: अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंगलवार को कच्चे तेल के उच्चतम स्तर पर बने रहने के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार दूसरे दिन टिकाव रहा। रविवार को लगातार पांचवें दिन 35-35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 107.59 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.32 रुपए प्रति लीटर के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। मुंबई में पेट्रोल 113.46 रुपए और डीजल 104.38 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल सबसे महंगा 116.26 रुपए प्रति लीटर पर और डीजल 105.64 रुपए प्रति लीटर पर, पटना में पेट्रोल 111.24 रुपए और डीजल 102.93 रुपए प्रति लीटर, बेंगलुरू में पेट्रोल 111.34 रुपए और डीजल 102.23 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। रांची में पेट्रोल 101.89 रुपए और डीजल 101.63 रुपए प्रति लीटर पर है। दिल्ली एनसीआर के नोएडा में पेट्रोल 104.76 रुपए और डीजल 96.47 रुपए प्रति लीटर पर है। अभी देश के अधिकांश प्रमुख बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर को पार कर चुकी है और डीजल भी शतक लगाने की ओर बढ़ रहा है। इस महीने में अब तक 26 दिनों में से 19 दिन इन दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। इस महीने में अब तक पेट्रोल 5.95 रुपए प्रति लीटर और डीजल 6.55 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मंगलवार को सिंगापुर में कच्चे तेल में कारोबार नरमी के साथ शुरू हुआ। ब्रेंट क्रूड 0.06 प्रतिशत नरम पड़कर तीन वर्ष के उच्चतम स्तर 85.94 डॉलर प्रति बैरल पर और अमेरिकी क्रूड 0.13 प्रतिशत उतरने के बावजूद अक्टूबर 2014 के बाद सात वर्ष के उच्चतम स्तर पर 83.65 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार, दिल्ली में पेट्रोल 107.59 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.32 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। पेट्रोल-डीजल के मूल्यों की रोजाना समीक्षा होती है और उसके आधार पर हर दिन सुबह छह बजे से नई कीमतें लागू की जाती हैं।

चीन सरकार की आलोचना जैक मा को पड़ी भारी, Alibaba ने एक साल में गंवाए 344 अरब डॉलर

(एजेंसी)

चीन की बड़ी कंपनियों में से एक अलीबाबा के मार्केट कैप में एक साल में 344 अरब डॉलर की कमी आई है। दरअसल पिछले साल अक्टूबर में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने चीन की वित्तीय प्रणाली की आलोचना की थी। इसके बाद तो उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। चीन की सरकार ने उनकी कंपनी अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पहले फिनटेक कंपनी **Ant Group** की लिस्टिंग सस्पेंड कर दी और फिर टेक कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की। इससे देश की टेक कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई। इससे एक साल में अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग का मार्केट कैप 344 अरब डॉलर कम हो गया। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी का शेयर

ऑल टाइम हाई पर था लेकिन 3 हफ्ते पहले हॉन्ग कॉन्ग में यह रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया। चीन सरकार ने कंपनी के खिलाफ जांच तेज कर दी है और साथ ही उसे फिनटेक बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करने को कहा गया है। 5 अक्टूबर के बाद से इसमें 30 फीसदी रिकवरी हुई है लेकिन अब भी यह पिछले साल अक्टूबर के लेवल से 43 फीसदी कम है। अलीबाबा 5 नवंबर को अपने वित्तीय नतीजों की घोषणा करेगी। अलीबाबा के शेयरों में गिरावट से जैक मा की नेटवर्थ में भी गिरावट आई है। एक वक्त वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी को पछाड़कर एशिया के सबसे बड़े रईस बन गए थे लेकिन आज वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 30वें स्थान पर खिसक गए हैं। उनकी नेटवर्थ 45.9 अरब डॉलर है। दूसरी ओर अंबानी 98.2 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ एशिया में पहले और दुनिया में 11वें नंबर पर हैं।

सेबी ने फोर्टिस हेल्थकेयर पर 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया

नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फोर्टिस हेल्थकेयर होल्डिंग्स पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर से जुड़े नियमों का उल्लंघन के लिए 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। सेबी ने सोमवार को एक आदेश में कहा कि कंपनी पर एलओडीआर (सूचीबद्धता दायित्व एवं खुलासा आवश्यकता) नियमों के कई प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। नियामक ने कहा कि फोर्टिस ने कुछ आईएसआईएन (इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर) के लिए ब्याज के भुगतान के बारे में जानकारी नहीं दी। आईएसआईएन कोड का इस्तेमाल विशिष्ट रूप से शेयर, बॉन्ड वारंट और वाणिज्यिक पत्रों जैसी प्रतिभूतियों की पहचान के लिए किया जाता है। सेबी ने कहा कि अन्य उल्लंघनों के अलावा कंपनी ने एनसीडी (गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर) धारकों को वार्षिक रिपोर्ट की प्रति प्रदान नहीं की, जबकि उन्होंने इसके लिए अनुरोध किया था। इसके अलावा कंपनी को मानदंडों के तहत निर्दिष्ट ब्याज, लाभांश आदि के भुगतान के लिए रिकॉर्ड तारीख तय करने की जरूरत थी लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रही।

अडाणी समूह श्रीलंका के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है: अधिकारी

कोलंबो: कोलंबो बंदरगाह के पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने और चलाने के लिए श्रीलंका के साथ एक समझौता करने वाला अडाणी समूह अब वहां नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाश रहा है। श्रीलंका सरकार के सीलोन बिजली बोर्ड (सीईबी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि यह निवेश पवन ऊर्जा क्षेत्र में किया जा सकता है। यह टिप्पणी अडाणी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से भेंट के एक दिन बाद आई। सूत्रों ने बताया कि एक निजी यात्रा पर श्रीलंका आए अडाणी ने राष्ट्रपति राजपक्षे से मुलाकात की, हालांकि उन्होंने बैठक का कोई ब्यौरा नहीं दिया। सीईबी के उपाध्यक्ष नलिंदा इलंगाकून ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''अडाणी समूह ने कल श्रीलंका के पवन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं तलाशी। इलांगकून ने कहा कि अडाणी समूह के वरिष्ठ अधिकारियों ने सोमवार को उत्तर पूर्वी जिले मन्नार का दौरा किया और वहां पवन ऊर्जा फार्म का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गौतम अडाणी और 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका वायु सेना के हेलीकॉप्टर से मन्नार की यात्रा की।

एलन मस्क ने रचा इतिहास, सिर्फ एक दिन में कमाए रिकॉर्ड 2.71 लाख करोड़ रुपए

(एजेंसी)

इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने इतिहास रच दिया है। दरअसल, एलन मस्क की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है। सोमवार को एलन मस्क की दौलत में 2.71 लाख करोड़ रुपए (36.2 अरब डॉलर) की बढ़ोतरी हुई। यह किसी अमीर की दौतल में एक दिन में आई अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर्स इंडेक्स के अनुसार, मस्क की दौलत 289 अरब डॉलर हो गई है। सोमवार को टेस्ला का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ डॉलर को पार कर गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाली टेस्ला अमेरिका की छठी कंपनी है। सोमवार को कंपनी का शेयर 14.9 फीसदी बढ़कर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई 1,045.02 डॉलर पर पहुंच गई। शेयर में उछाल से एलन मस्क की दौलत बढ़ी। हट्र्ज ग्लोबल होल्डिंग्स ने 100,000 टेस्ला कारों ऑर्डर दिया है। 1 लाख कारों के ऑर्डर मिलने से टेस्ला के शेयरों में शानदार तेजी आई। टेस्ला में मस्क की 23 फीसदी हिस्सेदारी है। शेयर में तेजी से एक दिन में उनकी दौलत 2.71 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई।

इन कंपनियों से ज्यादा है मस्क की दौलत

इसके अलावा मस्क रॉकेट मेकर स्पेसएक्स के एक प्रमुख शेयरहोल्डर और सीईओ हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक निजी कंपनी जिसकी कीमत अक्टूबर सेकेंडरी शेयर बिक्री के रूप में 100 अरब डॉलर है। साल 2021 में मस्क की संपत्ति में 119 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। मस्क की कुल संपत्ति 289 अरब डॉलर है, जो अब एक्सॉन मोबिल कॉर्प या हृद्बद्ग ढ्ढठ्ठ के मार्केट वैल्यू से अधिक है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स के इतिहास में यह सबसे बड़ा वनडे गेन है। पिछले साल चीनी अरबपति झोंग शानशान की दौलत में 32 बिलियन डॉलर का उछाल आया था, जब उनकी बोतलबंद पानी कंपनी, नोंगफू स्प्रिंग कंपनी **(Nongfu Spring Co)** लिस्ट हुई थी।

'कू' ने टी-20 विश्वकप में शुरू किया अभियान, आपने #KooKiyaKya

(एजेंसी)

भारत के प्रमुख बहु-भाषा माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म कू **(Koo)** ने लोगों को अपनी मातृभाषा में खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाने के लिए अपना पहला टेलीविज़न अभियान शुरू किया है। यह अभियान यूज़र्स की स्व-अभिव्यक्ति के लिए सोशल मीडिया का लाभ उठाने और अपनी पसंद की भाषा में अपने समुदायों से जुड़ने और जुड़ने की इच्छा की छवि है। टी-20 विश्व कप 2021 की शुरुआत में शुरू किया गया अभियान ओगिल्वी इंडिया द्वारा परिकल्पित शॉर्ट-फॉर्मेट की 20 सेकंड के विज्ञापनों की एक श्रृंखला है, जो टैगलाइन **#KooKiyaKya** के इर्द-गिर्द अपनी विचित्रता, विवेकपूर्ण और मज़ाक़ के माध्यम से दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती हैं। अपने दैनिक जीवन के बारे में बताते हुए दिलचस्प दृश्य, हल्के-फुल्के मज़ाक में लिप्त होकर और आकर्षक मुहावरों के द्वारा अपने दिल की सीधे बात कू**(Koo)** के ज़रिए उन्हें ऑनलाइन व्यक्त किया जा सकता है। विज्ञापन एक एकीकृत संदेश के इर्द-गिर्द बुने जाते हैं - अब दिल में जो भी हो, कू**(Koo)** पे कहो। यह अभियान इंटरनेट यूज़र्स के दिमाग को डिकोड करने और उनकी मूल भाषा में कंटेन्ट को डिजिटल रूप से साझा करने और उनकी इच्छा को समझने के लिए गहन शोध और बाजारी मानचित्रण का अनुसरण करता है। यह विज्ञापन प्रमुख खेल चैनलों पर लाइव हैं और टी20 विश्व कप मैचों के दौरान चलाए जाएंगे। कू**(Koo)** ऐप के सह-संस्थापक और सीईओ प्रेमेय राधाकृष्ण ने कहा, कू**(Koo)** भाषा-आधारित माइक्रो-ब्लॉगिंग की दुनिया में एक खोज है। हम अपने मंच पर अपनी पसंद की भाषा में विचार साझा करने के लिए विभिन्न संस्कृतियों के लोगों को एक साथ लाते हैं। यह अभियान एक दिलचस्प अंतर्दृष्टि के इर्द-गिर्द तैयार किया गया है जो आपकी मातृभाषा में व्यक्त करने की आवश्यकता को दर्शाता है। यह कू**(Koo)** को एक समावेशी मंच के रूप में स्व-अभिव्यक्ति के लिए एक मंच के रूप में स्थान देता है जो उन लोगों को आवाज़ देता है जिन्होंने पहले कभी भाषा-आधारित सोशल मीडिया का अनुभव नहीं किया है। टी20 विश्व कप 2021 अभी हो रहा है, ऐसे में यह सही समय है कि हम लोगों को एक-दूसरे से सार्थक रूप से जुड़ने में मदद करने के लिए अपने संदेश को प्रसारित करने के लिए एक प्रमुख चैनल के रूप में टेलीविजन का लाभ उठाएं।

हमें विश्वास है कि यह अभियान हमारे ब्रांड रिकॉल को बढ़ाएगा, अपनाने में तेजी लाएगा और हमारे प्लेटफॉर्म को लोगों के डिजिटल जीवन का एक अभिन्न पहलू बनाने के लिए 'कू' की यात्रा में वास्तव में सार्थक भूमिका निभाएगा। 'कू' के सह-संस्थापक मयंक बिदावतका ने कहा, भारत में हर किसी की किसी न किसी बात को लेकर अपनी राय होती है। ये विचार और राय करीबी या सामाजिक मंडलियों तक सीमित हैं और बड़े पैमाने पर ऑफ़लाइन हैं। इन विचारों को लोगों की पसंदीदा भाषा में व्यक्त करने के लिए भारत के एक बड़े हिस्से को ऑनलाइन सार्वजनिक मंच नहीं दिया गया है। यह अभियान इसी के बारे में है- प्रत्येक भारतीय को अपनी मातृभाषा में अपने विचार साझा करना शुरू करने और कू**(Koo)** पर लाखों अन्य लोगों के साथ सार्थक तरीके से जुड़ने का निमंत्रण। अभियान वास्तविक जीवन की स्थितियों और बातचीत को दर्शाता है। 'कू' को बड़े पैमाने पर भारत के लिए बनाया गया है और हम ध्यान आकर्षित करने के लिए मशहूर हस्तियों का उपयोग करने की लहर में देने के बजाय अपने विज्ञापनों में वास्तविक लोगों को दिखाना चाहते थे। हम बड़े पैमाने पर भारत के साथ भाषा-आधारित विचार साझा करने के अपने मूल प्रस्ताव को लेकर बहुत उत्साहित हैं। ओगिल्वी इंडिया के हमारे भागीदारों ने इस अवधारणा को जीवंत करने का शानदार काम किया है! सुकेश नायक चीफ क्रिएटिव ऑफिसर ओगिल्वी इंडिया ने कहा, हमारा विचार जीवन से आया है। जब हम अपने दोस्तों या परिवार से अपनी भाषा में बात करते हैं तो हमें खुद को सबसे अच्छा व्यक्त कर पाते हैं।

1 जुलाई से केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा 31% महंगाई भत्ता : वित्त मंत्रालय

(एजेंसी)

वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को मूल वेतन के 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया है, जो एक जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले व्यय विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि 'मूल वेतन' का अर्थ 7वें वेतन आयोग के अनुसार प्राप्त वेतन है और इसमें कोई अन्य विशेष वेतन या भत्ता शामिल नहीं है। व्यय विभाग ने 25 अक्टूबर को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा, ''केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 1 जुलाई, 2021 से मूल वेतन के मौजूदा 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 31 प्रतिशत किया जाएगा।'' यह बढ़ोतरी रक्षा सेवाओं से वेतन पाने वाले असैन्य कर्मचारियों पर भी लागू होगी, जबकि सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में रक्षा और रेल मंत्रालय अलग से आदेश जारी करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को मौजूदा 28 फीसदी

से तीन प्रतिशत बढ़ाने को मंजूरी दी थी। इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47.14 लाख कर्मचारियों और 68.62 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। इस साल जुलाई में डीए की दर 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी गई थी।

अब तीन फीसदी की बढ़ोतरी के साथ डीए की दर 31 फीसदी हो जाएगी। महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के कारण राजकोष पर कुल 9,488.70 करोड़ रुपए का असर होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर, चालू वित्त वर्ष में 9.5% रहेगी भारत की ग्रोथ रेट

(एजेंसी)

भारतीय अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 9.5 फीसदी की दर से बढ़ेगी। 2020-21 में इसमें 7.3 प्रतिशत गिरावट आई थी। स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया ने कहा कि दबी मांग और टीकाकरण से चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था और रफ्तार पकड़ेगी। हालांकि, 2022-23 में वृद्धि दर घटकर 7.7 प्रतिशत रहने का अनुमान है। दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी।

सरकार ने बजट में चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था में 10.5 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है। हालांकि, आरबीआई ने अपने वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 9.5 प्रतिशत कर दिया है।

इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 67.6 हजार करोड़ पार

देश के इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात सितंबर, 2021 में 9 अरब डॉलर (67.6 हजार करोड़ रुपए) के पार पहुंच गया। इस दौरान चीन, ब्रिटेन और यूएई जैसे शीर्ष-25 निर्यात गंतव्यों में से 22 में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। आलोच्य महीने में कुल वस्तुओं के निर्यात में इंजीनियरिंग वस्तुओं की हिस्सेदारी 26.65 फीसदी रही। इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद के मुताबिक, 2021-22 में निर्यात 105 अरब डॉलर रहने का अनुमान है।

टेलीकॉम कंपनियों को राहत देने के लिए मोदी सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम

(एजेंसी)

सरकार ने सोमवार को दूरसंचार लाइसेंस नियमों में संशोधन किया। इसके तहत सभी गैर-दूरसंचार राजस्व, लाभांश, ब्याज, संपत्ति बिक्री और किराए समेत अन्य को लाइसेंस शुल्क तथा स्पेक्ट्रम प्रयोग शुल्क की गणना से बाहर किया गया है। इसका उद्देश्य दूरसंचार परिचालकों पर कर बोझ को कम करना है। संशोधन केंद्र सरकार द्वारा घोषित दूरसंचार पैकेज का हिस्सा है।

उल्लेखनीय है कि समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) की पुरानी परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इससे भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत दूरसंचार सेवाप्रदाताओं पर करीब 1.47 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। दूरसंचार विभाग के सोमवार को किए गए संशोधन के तहत कंपनियों के सकल राजस्व में से इन स्रोतों की आय को घटाने के बाद लागू समायोजित सकल राजस्व (एपीजीआर) की गणना की जाएगी। इसके बाद पुराने नियमों के तहत पहले से छूट वाली श्रेणियों मसलन रोमिंग आय, इंटरकनेक्शन शुल्क और माल और सेवा कर को घटाया जाएगा और फिर अंतिम एजीआर निकाला जाएगा। इसके आधार पर सरकार राजस्व में अपनी हिस्सेदारी की गणना करती है। दूरसंचार विभाग ने कहा, ''संशोधन एक अक्टूबर, 2021 से प्रभाव में आ गया है।

और उक्त तिथि के बाद लाइसेंसधारक के संचालन से जुड़ी बकाया राशि पर लागू होगा।'' विभिन्न गैर-दूरसंचार राजस्व के स्रोतों पर छूट से शुल्कों में उल्लेखनीय कमी की उम्मीद है।

सितंबर तिमाही में कोटक महिंद्रा बैंक का शुद्ध मुनाफा 7% घटकर 2,032 करोड़ रुपए

नई दिल्ली (एजेंसी):

निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने मंगलवार को बताया कि सितंबर 2021 को समाप्त दूसरी तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा लगभग सात प्रतिशत घटकर 2,032 करोड़ रुपए रह गया। पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में बैंक ने 2,184 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया था। कोटक महिंद्रा बैंक ने शेयर बाजार को बताया कि वर्ष 2021-22 की जुलाई-सितंबर अवधि के दौरान कुल आय बढ़कर 8,408.87 करोड़ रुपए हो गई, जबकि वित्त वर्ष 2020-21 की समान अवधि में यह 8,252.71 करोड़ रुपए थी। वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में बैंक की शुद्ध ब्याज आय, वित्त वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही के 3,897 करोड़ रुपए से तीन प्रतिशत बढ़कर 4,021 करोड़ रुपए हो गई। तिमाही के दौरान शुद्ध ब्याज मार्जिन 4.45 प्रतिशत था। परिसंपत्ति के मोर्चे पर, बैंक की सकल गैर-निष्पादित आस्ति (या खराब ऋण या एनपीए) सितंबर 2021 तिमाही के अंत तक 3.19 प्रतिशत हो गई जो एक साल पहले की समान अवधि के अंत तक 2.55 प्रतिशत थी। बैंक का शुद्ध एनपीए 0.64 प्रतिशत से बढ़कर 1.06 प्रतिशत पर था। सितंबर तिमाही के लिए बैंक के फंसे हुए ऋणों और आकस्मिकताओं के प्रावधानों को एक साल पहले की तिमाही में अलग रखे गए 333.22 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 423.99 करोड़ रुपए कर दिया गया था।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान की जीत पर तालिबान ने दी बधाई

नई दिल्ली। टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान की पहली जीत पर तालिबान ने बधाई दी है। बता दें कि अफगानिस्तान ने सोमवार को स्कॉटलैंड को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में बुरी तरह से हराया। तालिबान के कब्जे के बाद यह अफगानिस्तान की पहली सबसे बड़ी जीत है।तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद ने ट्विटर पर लिखा, अफगानिस्तान की जीत पर टीम को बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अगस्त में अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद संदेह था कि टीम टी20 विश्व कप में भाग लेगी या नहीं। इसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी) के अध्यक्ष अजीजुल्लाह फाजली ने स्पष्ट किया था कि टीम टूर्नामेंट में भाग लेगी। टी20 विश्व कप में अफगानिस्तान की टीम बड़ी जीत के बाद सुपर 12 के ग्रुप 2 के शीर्ष पर पहुंच गई है जबकि दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है।

ओलंपिक (महिला हॉकी)

स्टेडियम में दर्शकों की गैरमौजूदगी में होगा FIH जूनियर हॉकी विश्व कप

भुवनेश्वर (एजेंसी) ।

पुरुषों का एफआईएच हॉकी जूनियर विश्व कप यहां 24 नवंबर से खाली स्टेडियम में खेला जाएगा क्योंकि आयोजकों को लगता है कि अगर दर्शक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं तो कोविड-19 नियमों को लागू करना मुश्किल होगा। जूनियर स्तर की यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता यहां कलिंगा स्टेडियम में 24 नवंबर से पांच दिसंबर तक खेली जाएगी। मेजबान भारत टूर्नामेंट का गत चैंपियन है। हॉकी इंडिया ने कहा कि इस क्षेत्र में खेल की लोकप्रियता को देखते हुए स्टेडियम में दर्शकों के पहुंचने की उम्मीद है, आयोजकों का मानना है कि जरूरी कोविड दिशानिर्देश और नियमों का पालन करते हुए बड़ी संख्या में लोगों को नियंत्रित करना संभव नहीं होगा। कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए सामाजिक दूरी प्राथमिकता है और प्रशंसकों तथा खिलाडियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है। ऐसे माहौल में टूर्नामेंट का आयोजन अतिआवश्यक है जहां प्रतिस्पर्धी टीमों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च महत्व दिया जाए। कलिंगा स्टेडियम सिर्फ मान्यता प्राप्त लोगों और टूर्नामेंट के प्रतिभागियों के लिए खुला रहेगा। टूर्नामेंट में 16 टीमें हिस्सा लेंगी जिसमें मेजबान भारत के अलावा अर्जेन्टीना, बेल्जियम, कनाडा, चिली, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, कोरिया, मलेशिया, पाकिस्तान, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, नीदरलैंड और अमरीका शामिल हैं। पांच दिन तक पूल चरण के मैचों के आयोजन के बाद 30 नवंबर से क्लासिफिकेशन मुकाबले होंगे। क्वार्टर फाइनल मुकाबले एक दिसंबर को, सेमीफाइनल मुकाबले तीन दिसंबर और फाइनल 5 दिसंबर को होगा। विदेशी टीमों को पृथकवास से छूट दी गई है और

यहां रहने के दौरान उन्हें कोविड-19 लक्षणों को लेकर अपना निरीक्षण करने की जरूरत है। उन्हें कोविड-19 से जुड़े जरूरी स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। मेहमान टीमों को जिन अनिवार्य स्वास्थ्य सुरक्षा नियमों को मानना होगा उनमें से सभी प्रतिभागियों का यहां पहुंचने से पहले आरटी-पीसीआर कोविड-19 परीक्षण शामिल है जो रवानगी से 72 घंटे कि भीतर किया गया हो। इसके अलावा यूरोप और पश्चिमी एशिया से आने वाली टीमों का हवाई अड्डे पर पहुंचने पर अनिवार्य परीक्षण शामिल है।

निक्की पूनाचा, पारस दहिया राष्ट्रीय टेनिस चैम्पियनशिप के अगले दौर में पहुंचे

नई दिल्ली (एजेंसी)।

शीर्ष वरीयता प्राप्त और पूर्व चैंपियन निक्की पूनाचा ने फेनेस्टा ओपन राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप में साई कार्तिक रेड्डी जबकि पारस दहिया ने करण सिंह को हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। पूनाचा ने पुरुष एकल के शुरुआती मैच में रेड्डी को 6-4 6-3 से हराया। चौथी वरीयता प्राप्त दहिया को यहां के डीएलटीए परिसर में करण सिंह को 6-2, 7-5 से हराने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। तीसरी वरीयता प्राप्त नितिन कुमार सिन्हा को नीरज यशपॉल पर 6-1, 6-1 से जीत दर्ज करने में कोई परेशानी नहीं हुई। महिला एकल में वंशिता पठानिया ने आठवीं वरीयता प्राप्त प्रेरणा भांबरी को 2-6, 7-5, 6-1 से हराया। श्रुति अहलावत ने पूजा इंगले को 6-0, 6-2 से जबकि फरहत अलीन कमर ने शेफाली अरोड़ा को 6-2, 6-0 से शिकस्त दी। दूसरी वरीयता प्राप्त वैदेही चौधरी ने नियति कुकरेती को 6-3, 6-0 और तीसरी वरीयता प्राप्त श्रावण्या शिवानी ने सी. श्रीनिधि को 6-3 7-5 से मात दी।

पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में शिवा थापा ने जीता पहला मुकाबला

नई दिल्ली।

पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मंगलवार को सर्बिया के बेलग्रेड में शिव थापा ने एक शानदार से जीत से टूर्नामेंट की शुरुआत की। थापा ने 64वें मैच में 63.5 किग्रा राउंड में केन्या के विक्टर न्यादेरा के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया और पूरे मैच के दौरान उन्होंने अपने विरोधी को नियंत्रण में रखा। थापा ने तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक आसान जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही पांच बार के एशियाई चैंपियनशिप पदक विजेता थापा ने रोहित मोर और आकाश सांगवान के साथ मिलकर पहले दिन टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज किया। थापा अब शनिवार को सिएरा लियोन के जॉन ब्राउन से भिड़ेंगे। इसके साथ ही तीन और भारतीय मुक्केबाज अपने-अपने शुरुआती दौर के मैचों में भिड़ते नजर आएंगे। नरेंद्र (प्लस 92 किग्रा) का पोलैंड के ऑस्कर सफरन से जबकि सुमित (75 किग्रा) का जमैका के डेमन ओनील से मुकाबला होगा।

मलेशिया राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों की कर सकता है मेजबानी

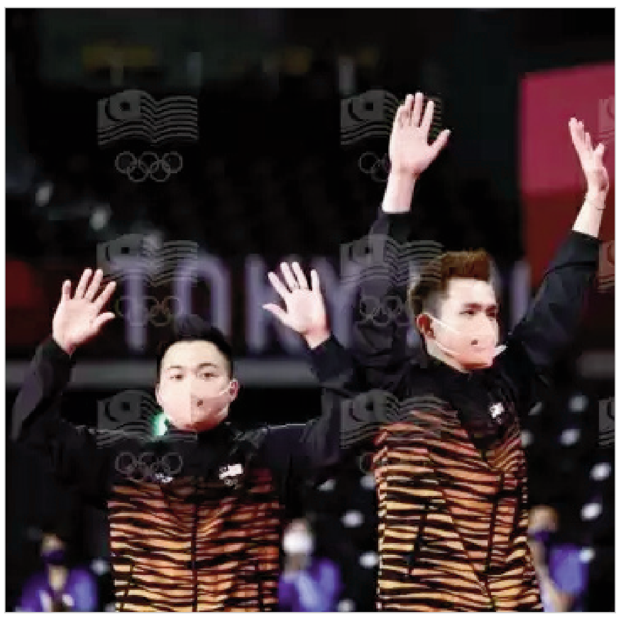

कुआलालंपुर (एजेंसी)।

मलेशिया ओलंपिक परिषद (ओसीएम) के उपाध्यक्ष दातो शाहरूल जमान याहया ने कहा, मलेशिया अगले 10-15 वर्षों में एशियाई खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करने के बारे में सोच रहा है, जिसे लेकर बातचीत चल रही है। बता दें कि पिछली बार 1998 में मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। वहीं, 2022 मेंएशियाई खेलों का आयोजन चीन तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम शहर में होने वाला हैं। उन्होंने कहा, खेलों की मेजबानी करना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए हमें पूरी योजना के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। हमें इसके लिए बोली लगाने के लिए तैयार रहना होगा। एशियाई खेलों की मेजबानी के लिए 2030 तक सभी स्लॉट भर दिए गए हैं। एशिया ओलंपिक परिषद (ओसीए) ने कतर और सऊदी अरब को 2030 और 2034 की जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए मलेशिया 2038 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए स्लॉट भर सकता है। याहया ने कहा, मैंने राष्ट्रमंडल खेलों का विस्तार होते देखा है। वहीं, इन खेलों में एथलीटों की संख्या हमेशा से बढ़ती रही हैं। यही कारण है कि मलेशिया 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कर सकता है।

संक्षिप्त समाचार

शेख रुसेल इंटरनेशनल ग्रांड मास्टर शतरंज - श्रीनाथ की बढ़त बरकरार

ढाका , बांग्लादेश (निकलेश जैन) शेख रुसेल इंटरनेशनल ग्रांड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में 7 राउंड के बाद भारत के श्रीनाथ नारायनन नें अजरबैजान के ग्रांड मास्टर इसकानदारोव मिसरातदिन से ड्रॉ खेलते हुए अपनी एकल बढ़त को कायम रखा है और ख़िताबी दौड़ मे सबसे आगे बने हुए है । प्रतियोगिता मे अब तक श्रीनाथ नें 6 अंक बना लिए है और इस दौरान 5 जीत दर्ज की है जबकि 2 मुक़ाबले अनिर्णीत रहे है । हालांकि इस ड्रॉ से श्रीनाथ की बढ़त अब आधा अंक की रह गयी है क्यूंकी उक्रेन के वितालय बेरनाड्स्किय नें ईरान के मौसवी सैयद खलील को ,रासूलोव नें भारत के स्टेनी जीए को और ईरान के मौसूद मौसादेघपौर नें भारत के विसाख एनआर को मात देते हुए 5.5 अंक बना लिए है । राउंड 8 में श्रीनाथ के सामने अब रासूलोव होंगे जबकि ईरान के मौसूद और उक्रेन के वितालय को वह पहले ही मात दे चुके है अन्य भारतीय खिलाड़ियों में श्याम सुंदर नें आज हमवतन आदित्य मित्तल से ड्रॉ खेला और अब आदित्य ग्रांड मास्टर नार्म हासिल करने के और करीब आ गए है । मित्रभा गुहा नें अजरबैजान के असदिल वुगार से बाजी ड्रॉ खेली ।

तमिलनाडु में होगा पुरुषों और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नेत्रहीन फुटबॉल टूनार्मेंट का आयोजन

चेन्नई। तमिलनाडु पहली बार 27-30 अक्टूबर तक चलने वाले पुरुषों और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय नेत्रहीन फुटबॉल टूनार्मेंट का आयोजन करने जा रहा है। तमिलनाडु ने 2018 में पुरुषों के लिए एक नेत्रहीन फुटबॉल टीम बनाई थी। 2019 में नेत्रहीन फुटबॉल संघ ने इस पर काम करना शुरू कर दिया था। टीएन ब्लाइंड फुटबॉल एसोसिएशन के संस्थापक, जीआर भारतीराजा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, हम 27 अक्टूबर से पुरुषों और महिलाओं के लिए राष्ट्रीय फुटबॉल चैम्पियनशिप की मेजबानी करने जा रहे हैं। हमें टीम के साथ एसोसिएशन बनाने में थोड़ी देरी हो गई, लेकिन हमने एक अच्छी टीम तैयार कर ली है, जो इस टूर्नामेंट में खेलेगी। ऐसा पहली बार है जब एक राष्ट्रीय स्तर पर महिला नेत्रहीन फुटबॉल टूनार्मेंट का आयोजन किया जा रहा है, जबकि यह पुरुष टीम के लिए छठा टूनार्मेंट होगा। उन्होंने कहा, टूर्नामेंट 2023 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन संघों ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों पर दबाव डाल कर 2021 में ही टूनार्मेंट को करवाने को कहा। महिला और पुरुषों की टीमों को फ्रांसिस सेबेस्टियन ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि एक बेतहरीन कोच हैं। भारतीराजा और सेबेस्टियन ने कहा, खेलों को कराने में ढांचागत समस्याएं आ रही हैं क्योंकि टीम के पास खेल को कराने के लिए अपना मैदान नहीं है, लेकिन खेलों के प्रति सभी में जूनून देखकर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है।

पाकिस्तान के खिलाफ शानदार पारी के लिए गावस्कर ने की कोहली की तारीफ

दुबई (एजेंसी)।

महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने पाकिस्तान के खिलाफ टी20 विश्व कप में भारतीय कप्तान विराट कोहली की 57 रन की पारी की तारीफ करते हुए कहा कि कठिन हालात में खेली गई यह शानदार पारी थी। कोहली ने पांच चौकों और एक छक्के की मदद से 49 गेंद में 57 रन बनाए लेकिन भारत को पाकिस्तान ने दस विकेट से हरा दिया। विश्व कप में पाकिस्तान की भारत पर यह पहली जीत थी। गावस्कर ने कहा कि यह शानदार पारी थी क्योंकि भारत ने पावरप्ले में ही सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए थे लिहाजा कोहली के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी । उसे पारी को ढर्रे पर लाना था और रनगति भी बढ़ानी थी।कोहली ने जिस तरह से पारी खेली, वह अद्भुत थी और खासकर शाहीन अफरीदी को जो छक्का लगाया, वह कमाल का था। गावस्कर ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में वह गेंदबाजी कर रहा था, दाहिने हाथ से सही कोण बनाकर गेंद डालने के बाद वह स्विंग का जैसे इस्तेमाल कर रहा था। ऐसे में कोहली का इस तरह से खेलना जरूरी था। बाहर निकलकर खेलने से ही वह अफरीदी के सामने रन बना सका। पूर्व बल्लेबाज वीवीएस

लक्ष्मण ने कहा कि पाकिस्तान से मिली हार से तीन सबक मिलते हैं। उन्होंने कहा कि पहला सबक यह कि पावरप्ले में विकेट नहीं गंवाना है क्योंकि फिर आप इसका फायदा नहीं उठा सकते। इसी तरह गेंदबाजी करते हुए पावरप्ले में विकेट लेना है खासकर जब आपने ज्यादा रन नहीं बनाए हैं। इसके अलावा गेंदबाजों का विविधता का इस्तेमाल करना जरूरी है।

टी20 विश्वकप से बाहर हुए लॉकी फर्ग्यूसन, उनकी जगह लेगा यह तेज गेंदबाज

शारजाह ।

न्यूजीलैंड के टी20 विश्व कप अभियान को बड़ा झटका लगा जब मंगलवार को पाकिस्तान के खिलाफ टीम के पहले मैच से पूर्व तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन पिंडली में 'ग्रेड टू% की चोट के कारण इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता से बाहर हो गए। तेज गेंदबाज एडम मिल्ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की तकनीकी समिति से स्वीकृति मिलने पर 15 सदस्यीय टीम में उनकी जगह लेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने कहा कि 30 साल के फर्ग्यूसन को सोमवार रात ट्रेनिंग के बाद दाईं पिंडली में जकड़न महसूस हुई। इसके बाद एमआरआई स्कैन कराया गया जिसमें ग्रेड टू चोट का खुलासा हुआ जिससे उबरने में तीन से चार हफ्ते का समय लगेगा। मुख्य कोच गैरी स्टीड ने बयान में कहा कि टूर्नामेंट की पूर्व संध्या पर ऐसा होना लॉकी के लिए निराशाजनक है और पूरी टीम फिलहाल उनके लिए निराश है। न्यूजीलैंड को अगले 13 दिन में पांच पूल मैच खेलने हैं और कोच स्टीड ने कहा कि ऐसे में उनके पास फर्ग्यूसन को टूर्नामेंट से बाहर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह हमारी टी20 टीम का अहम हिस्सा है और काफी अच्छी फॉर्म में था इसलिए इस समय उसे गंवाना बड़ा झटका है। हालांकि हम भाग्यशाली है कि एडम के रूप में हमारे पास उनके समान विकल्प है जो पिछले दो हफ्ते से टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। मिल्ने यूएई में ही मौजूद हैं क्योंकि न्यूजीलैंड ने टीम में उन्हें चोट की स्थिति में कवर के रूप में शामिल किया था। वह हालांकि आईसीसी से स्वीकृति मिलने पर ही उपलब्ध होंगे।

दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटरों को विश्व कप मैचों से पहले घुटने के बल बैठने के निर्देश

दुबई । दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट बोर्ड ने अपने खिलाड़ियों को टी20 विश्व कप मैचों से पहले नस्लवाद के खिलाफ आंदोलन का घुटने के बल बैठकर समर्थन जताने का निर्देश दिया है। सीएसए ने सोमवार की शाम सर्वसम्मति से इस पर रजामंदी जताई कि दक्षिण अफ्रीका के सभी खिलाड़ी बाकी मैचों की शुरूआत से पहले घुटने के बल बैठेंगे। बोर्ड ने कहा कि सभी संबंधित मसलों पर गौर करने के बाद बोर्ड का यह मानना है कि दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को देखते हुए नस्लवाद के खिलाफ एकजुट और लगातार विरोध प्रदर्शन जरूरी है। इससे पहले भारतीय टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को पहले मैच से पूर्व 'ब्लैक लाइव्स मैटर' वैश्विक मुहिम के तहत घुटने के बल बैठकर नस्लवाद का विरोध किया था।

मार्करम की धमाकेदार पारी, द. अफ्रीका ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया

(एजेंसी) ।

साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 सुपर 12 ग्रुप 1 का मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बवुमा ने टॉस जीत लिया है और पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। पहले बल्लेबाजी के लिए आई वेस्टइंडीज की टीम ने एविन लुईस की अर्धशतकीय पारी की मदद से 143 रन बनाने में कामयाब हो पाई और दक्षिण अफ्रीका के सामने 144 रन का लक्ष्य रखा। जिसे दक्षिण अफ्रीका की टीम ने डुसेन और मार्करम की साझेदारी के बदौलत हासिल कर लिया। मार्करम ने नाबाद 26 गेंदों पर 51 रन की पारी खेली जिसमें उन्होंने 4 छक्के लगाए। दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच को 8 विकेट से जीतकर टूर्नामेंट की पहली जीत हासिल की।

दक्षिण अफ्रीका

डुसेन 51 गेदों पर 43 रन की पारी खेली तो वहीं मार्करम ने 26 गेंदों पर 56 रन की पारी खेलकर टीम की जीत में अहम योगदान दिया। दो विकेट गंवाने के बाद डुसेन और ऐडन मार्करम ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को संभाला और रन बटोरने शुरू किए। दोनों ही बल्लेबाजों ने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और टीम को जीत दिला दी।

हेंडरिक्स और डुसेन की अर्धशतकीय साझेदारी को अकेल हुसैन ने तोड़ा। हुसैन हैंडरिक्स को 39 रन पर आउट कर टीम को दूसरी सफलता दिलाई।

लक्ष्य का पीछा करने आई दक्षिण अफ्रीका टीम की शुरूआत अच्छी नहीं रही और कप्तान बवुमा 2 रन बनाकर रन आउट हो गए। पहला विकेट जल्दी गंवाने के बाद हेंडरिक्स और डुसेन ने पारी को संभाला।

वेस्टइंडीज

शिमरॉन हेटमायर एक रन बनाकर रन आउट हो गए। इसके बाद कप्तान पोलार्ड 26 रन बनाकर प्रिटोरियस की गेंद पर डुसेन को कैच थमा बैठे। अगली ही गेंद पर वॉल्श शून्य पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद बाद प्रिटोरियस ने गेल को 12 रन पर आउट कर चलता किया और दक्षिण अफ्रीका की टीम को चौथी सफलता दिलाई। बल्लेबाजी के लिए आंद्रे रसल को 5 रन पर आउट कर नोर्त्जे ने टीम को 5वीं सफलता दिलाई।

धीमी बल्लेबाजी कर रहे लेंडल सिमंस को आउट करके रबाडा ने वेस्टइंडीज की टीम को तीसरा झटका दिया। सिमंस ने 35 गेंदों पर 16 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका की टीम को दूसरी सफलता भी केशव महाराजा ने ही दिलाई।

महाराज ने निकोल्स पूरन को 12 रन पर मिलर का हाथों कैच आउट करवाया।

ओडेंसी में डेनमार्क ओपन बैडमिंटन मुकाबले में भाग लेती हुई दक्षिण कोरिया की शिन सयुंग और ली सो ही।

सिंगापुर में योरप जैसी शिक्षा कम खर्च, बेहतर सुविधा

सिंगापुर यूं तो विश्व के प्रमुख व्यवसायिक केंद्रों में से एक के रूप में ख्याति रखता है, लेकिन यह उच्च शिक्षा के लिहाज से भी एक अच्छा ऑप्शन है। योरप के मुकाबले सस्ता और भारत के निकट होने तथा यहां भारतीयों की बड़ी आबादी को देखते हुए यह भारतीय विद्यार्थियों के लिए अधिक आकर्षक बन जाता है। सिंगापुर के अलावा शायद ही कोई दूसरा स्थान हो, जहां पूर्व और पश्चिम दोनों की संस्कृतियों का समावेश देखने को मिले। कई सभ्यताओं और संस्कृतियों की छाप रखने वाला यह देश फाइनेंस, बिजनेस और एजुकेशन सभी क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। जहां तरह-तरह की विविधता हो, वहां सीखने के अवसर भी अधिक होते हैं। 'यह चीज सीख ली, चलो अब कुछ और सीखते हैं, ऐसी मानसिकता सिंगापुर के आम निवासियों की है। इस सोच के कारण ही सिंगापुर विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के नए मुकाम हासिल करता जा रहा है। यहां पढ़ने आने वाले विदेशी विद्यार्थी भी इस आदत को जल्द ही अपना लेते हैं। यह आदत जीवन के हर पल में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।

परदेस में भारत की झलक

सिंगापुर दक्षिण-पूर्व एशिया का एजुकेशन हब है और यह लगातार वैश्विक व्यापार का एक प्रमुख केंद्र भी बनता जा रहा है। यहां के अधिकतर विश्वविद्यालयों में एशियाई एवं पश्चिमी शिक्षण पद्धति का समावेश दिखाई देता है। शिक्षा के इस अनोखे समन्वय से आकर्षित होकर प्रतिवर्ष 80 हजार से अधिक विद्यार्थी विभिन्न विषयों का अध्ययन करने के लिए दूसरे देशों से यहां आते हैं। सिंगापुर में मलय, मंदारिन, तमिल और अंग्रेजी भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती हैं। यहां भारतीय तमिलों की संख्या बहुत अधिक है।

सिंगापुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजुकेशन हब के रूप में स्थापित करने के लिए यहां की सरकार शिक्षण-संस्थाओं को हर संभव सुविधा प्रदान करती है। यहां ट्यूशन फीस और रहने का खर्च बहुत अधिक नहीं है। सिंगापुर में उच्च शिक्षा की लागत योरपीय देशों की तुलना में कम ही है। इसके बाद भी शिक्षा की गुणवत्ता के मामले में यहां कोई समझौता नहीं किया जाता है।

परिवहन और खाने-पीने की चीजों के दाम भी मुनासिब ही हैं। बहुत-सी चीजों में स्टूडेंट आईकार्ड दिखाने पर कुछ छूट भी मिल जाती है। भारतीय विद्यार्थियों के लिए सिंगापुर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां से प्रमुख भारतीय शहरों में आने-जाने के साधन को लेकर कोई समस्या नहीं है। सिंगापुर से दिल्ली, मुंबई, चेन्नाई, कोलकाता आदि स्थानों के लिए अच्छी वायुसेवा आसानी से उपलब्ध है।

स्कॉलरशिप व अन्य छूट

अन्य प्रमुख देशों की तरह सिंगापुर में भी स्कॉलरशिप की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन स्कॉलरशिप्स से मिलने वाला धन ट्यूशन फीस के बोझ को काफी हद तक कम कर देता है। इसके अलावा विभिन्न योजनाओं के तहत विद्यार्थियों को चिकित्सा सेवाओं में भी भारी छूट मिल जाती है। यहां आने वाले विदेशी विद्यार्थी इस तरह की सहायता योजनाओं के लिए सिंगापुर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आवेदन कर सकते हैं।

आसान वीसा प्रक्रिया

सिंगापुर में शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ अमूमन सितंबर में होता है। विद्यार्थियों को स्टूडेंट वीसा बिना किसी खास परेशानी के निर्धारित प्रक्रिया के बाद मिल जाता है। स्टूडेंट वीसा के आवेदन के समय यह भी देखा जाता है कि आपकी अंग्रेजी पर पकड़ कैसी है। यदि अंग्रेजी अच्छी है, तो आपको यहां कोई असुविधा नहीं रहेगी।

प्रमुख शिक्षण संस्थान

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर
नानयांग यूनिवर्सिटी
नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी
सिंगापुर मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी
सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
एसआईएम यूनिवर्सिटी

इन फ्यूचर कोर्स में मिलेगी आपको मोटी सैलेरी

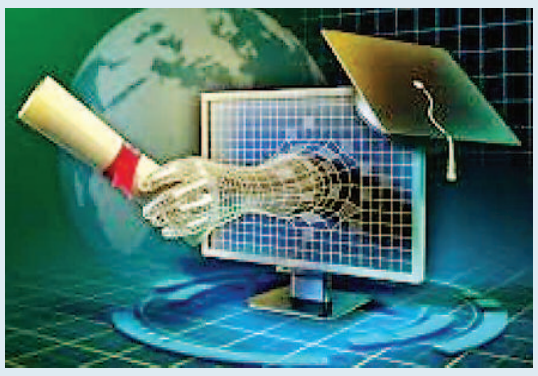

अगर आप एक तेजी से उभरती हुई इंडस्ट्री जैसे स्वच्छ ऊर्जा या आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो भविष्य में आपके पास अंत्रेप्रेन्योर बनने का अच्छा मौका है। लेकिन, हो सकता है कि इन क्षेत्रों में काम करने के लिए आपके पास जरूरी स्किल न हों। भविष्य पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर निर्भर होगा ऐसे में यह क्षेत्र आपको ज्यादा पैसे और तरक्की के अवसर प्रदान करेगा। अच्छी बात यह है कि अब इन नए क्षेत्रों में करियर बनाने के लिए कई नए कोर्स शुरू किए जा चुके हैं।

ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टोकरेंसिज

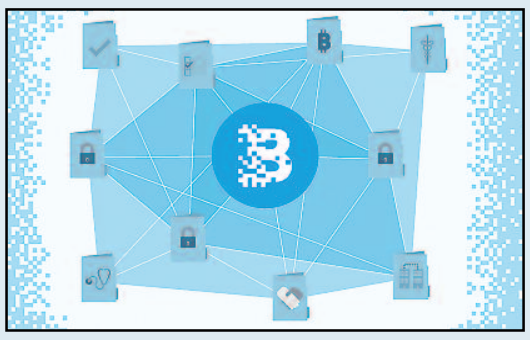

अगर आपने हाल ही में दुनिया के कई देशों पर हुए रैनसमवेयर हमले के बारे में सुना होगा तो आपको पता होगी कि हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉन की कीमत बढ़ गई है। बिटकॉन एक नई तकनीक का एक छोटा हिस्सा भर है। इस तकनीक को ब्लॉकचेन कहते हैं। ब्लॉकचेन एक डिजिटल फाइल की तरह है जहां क्रिप्टोकरेंसी द्वारा किए जाने वाले सारे भुगतान रिकॉर्ड किए जाते हैं। इससे पेमेंट करना और ज्यादा तेज व सुरक्षित हो जाता है। ये तकनीक अब दुनियाभर के बैंकों द्वारा इस्तेमाल में लाई जा रही है। जेपी मोरगन जैसे अंतरराष्ट्रीय बैंक अपने बैंकिंग सिस्टम को मॉर्डनाइज करने की कोशिश में जुटे हैं। कोर्सेरा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकी क्रिप्टोकरेंसी पर एक 11 हफ्ते का फ्री क्लास करवा रही है। इस क्लास में आपको क्रिप्टोकरेंसी के बारे में सारी जानकारियां दी जाएंगी।

औसत वेतन – 78 लाख सालाना

मशीन लर्निंग

मशीन लर्निंग का मतलब है कंप्यूटर को सोचना सीखाना। इसमें कंप्यूटर को ऐसा प्रोग्राम किया जाता है कि वो भारी भरकम डाटा और जानकारी का विश्लेषण कर सके। जैसे कंप्यूटर को भारी भरकम डाटा का विश्लेषण कर चेहरे खोजना, सामान की रिव्यू को समझना और हेल्थ डाटा को प्रोसेस करना सीखाया जाता है। स्टैनफोर्ड द्वारा डिजाइन कोर्सेरा का 11 हफ्तों का मशीन लर्निंग का कोर्स बेहद प्रसिद्ध है। इस कोर्स की कीमत महत 79 डॉलर यानि 5092 रुपये हैं। इस कोर्स को करीब 37 हजार रिव्यू के आधार पर पांच में से 49 का स्कोर हासिल है। इसमें सारी पढ़ाई विडियो लेक्चर से करवाई जाती है।

औसत वेतन – 01 करोड़ सालाना

वर्चुअल रीयालिटी विडियो प्रोडक्शन

2014 की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2017 में 74 फीसदी इंटरनेट ट्रैफिक विडियो पर होगा। ऐसे में इस साल को द इयर ऑफ ऑनलाइन विडियो कहना गलत नहीं होगा। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज और अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट के कारण विडियो पर ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में वर्चुअल रीयालिटी विडियो प्रोडक्शन के क्षेत्र में लोगों की मांग बढ़ रही है। एक ऑनलाइन मीडिया साइट वोकैटिव ने अपने सारे कंटेंट को विडियो में बदल दिया और उन्हें इसमें अपार सफलता मिली। विडियो एडिटिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन कई कोर्स मौजूद है। वहीं, लिंडा के लिंक डेन प्रोफाइल के ट्यूटोरियल प्लेटफॉर्म पर एक 35 घंटे का कोर्स करवाया जा रहा है। इसके लिए आपको कुछ पैसे जमा कर उनका स्स्कक्रिप्शन प्लान खरीदना पड़ेगा।

औसत वेतन – 50 लाख सालाना

फिटनेस इंस्ट्रक्शन

जो लोग शारीरिक फिटनेस को लेकर गंभीर है और वर्कआउट में यकीन रखते हैं उनके लिए भविष्य अवसरों से भरपूर है। फिटनेस इंडस्ट्री में हर दिन कोई न कोई नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनियाभर में मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में फिटनेस इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों में बड़ा बूम देखने को मिला है। शेप पाउंड नामक एक फिटनेस इंस्ट्रक्शन कोर्स चलाता है। इसमें ड्रमनुमा रिपस्टिक व्यायाम में लोगों को ट्रेन किया जाता है। इसके अलावा कार्डियो, कंडीशनिंग, स्ट्रेथ, योगा और पीलेट्स मूवमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा एनिमल फ्लो नामक कोर्स में जिमनास्टिक, एक्रोबेटिक्स, पारकोर, कौपोइरा और ब्रेकडासिंग सीखाई जाती है।

औसत कमाई – 26 लाख सालाना या ज्यादा

बडटेंडिंग

बडटेंडिंग मादक पदार्थों के वैध उत्पादन और इस्तेमाल से संबंधित पेशा है। गांजा जैसे मदाक पदार्थ यों तो दुनियाभर के ज्यादातर देशों में अवैध हैं, लेकिन दर्दनिवारक और अन्य कई दवाओं के निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। बडटेंडर उन विशेषज्ञों को कहते हैं जो मादक पदार्थों को उपजाने वाले और उनका दवाओं में प्रयोग करने वालों के बीच का काम करते हैं। टीएचसी यूनिवर्सिटी में बडटेंडिंग पर एक सर्टिफाइड कोर्स करवाया जाता है। यहां इस विषय में कुल आठ कोर्स कराए जाते हैं। इन कोर्सों को करने में 50 डॉलर प्रति महीने से लेकर 480 डॉलर प्रति महीने तक खर्च आता है।

औसत वेतन – मास्टर ग्रोअर – 46 लाख सालाना

बडटेंडर– 773 रुपए प्रति घंटे

इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी सिक्युरिटी

जितनी तेजी से आईटी क्षेत्र का प्रसार हुआ है उतनी ही तेजी से हैकिंग और साइबर सुरक्षा की समस्या भी उभर कर सामने आई है। निजता को बरकरार रखना और साइबर वर्ल्ड में जानकारियों को सुरक्षित रखना हर दिन चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में साइबर सिक्युरिटी और आईटी सिक्युरिटी के क्षेत्र में प्रोफेशनल लोगों की मांग बढ़ती जा रही है। आईटी सिक्युरिटी डिग्री प्रोग्राम अब कंप्यूटर साइंस के दूसरे विकल्पों के साथ भी पढ़ाई जा रही है। इस क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले लोगों को सबसे उच्च इंट्री लेवल वेतन मिलता है।

सर्वश्रेष्ठ स्पेशलाइजेशन– साइबर सिक्युरिटी, आईटी सिक्युरिटी, सिक्युरिटी एंड रिस्क एनालिसिस

औसत वेतन (सालाना) : 1.5 करोड़ (सॉफ्टवेयर सिक्युरिटी इंजीनियर), 1.3 करोड़ (सिक्युरिटी कंसल्टेंट), 1.1 करोड़ (साइबर सिक्युरिटी लीड)

एजुकेशन लोन डिफॉल्ट

छात्रों का क्रेडिट स्कोर हो सकता है खराब

सब्सिडी या कम ब्याज पर दिए गए एजुकेशन लोन में बढ़ रहे डिफाल्ट के मामलों के बारे में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी सिबिल कहा कि इस तरह की डिफॉल्ट हिस्ट्री छात्रों के क्रेडिट स्कोर पर विपरीत असर डाल सकती हैं जो कि उनकी ओर से भविष्य में लिए जाने वाले किसी अन्य लोन में मुसीबतें पैदा करेगा।

कम राशि में डिफॉल्ट के मामले ज्यादा

सिबिल ने बताया कि एजुकेशन लोन पर इस तरह के डिफॉल्ट मामले करीब 5 फीसदी हैं, जिनमें 90 दिनों से ज्यादा का ड्यूज है। कम ब्याज दरों पर 4 लाख से कम राशि के लोन के डिफॉल्ट के मामले (8.1 फीसदी) लंबी राशि के लोन के मुकाबले ज्यादा हैं। अन्य श्रेणियों के लिए तुलनात्मक डिफॉल्ट दरें हैं, 4 से 5 लाख के लिए 48 फीसदी और 5 से 15 लाख के लिए 2.1 फीसदी। वहीं 15 लाख के ऊपर की राशि के बड़े लोन पर डिफॉल्ट के मामले करीब 1 फीसदी हैं।

क्या होता है क्रेडिट स्कोर

आपका क्रेडिट स्कोर दरअसल आपकी ओर से पूर्व में लिए गए लोन और उसके चुकाने का ब्योरा भर होता है। बैंक आपके लोन की अर्जी को आपका क्रेडिट स्कोर चेक करने के बाद ही मंजूर करता है। अगर, अपका क्रेडिट स्कोर बेहतर है तो बैंक आपको आसानी से लोन मुहैया करा देते हैं।

क्या होता है क्रेडिट स्कोर और इसे कौन देता है

क्रेडिट स्कोर तीन अंको की एक संख्या होती है, जो 300 से 900 के बीच होती है। क्रेडिट स्कोर जितना अधिक होता है, उसे उतना ही बेहतर माना जाता है। एक डिफॉल्ट करने पर भी क्रेडिट स्कोर कमजोर हो सकता है। 79 फीसदी व्यक्तिगत लोन 750 से ज्यादा के स्कोर पर ही अप्रूव किए जाते हैं। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड क्रेडिट स्कोर देता है।

घर बैठे चेक करें अपना क्रेडिट स्कोर

आप सिबिल की वेबसाइट पर जाइए। यहां आपको एक फॉर्म भरना होगा। आपको शुल्क के रूप में 470 रुपए का भुगतान करना होगा। इसके बाद ऑथेन्टिकेशन के लिए आपसे पांच सवाल पूछे जाएंगे जिनमें से कम से कम तीन सवालों के सही जवाब आपको देने ही होंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद आप अपना क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं।

क्रांति समय

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

अफगानिस्तान में भुखमरी का भीषण संकट, श्रम के बदले गेहूं देने का किया ऐलान

नई दिल्ली। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश में भुखमरी और बेरोजगारी की समस्या एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। दिन पर दिन आर्थिक और मानवीय त्रासदी गहराती जा रही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने संकेत दिए हैं कि देश में नवंबर महीने में खाद्य संकंट और ज्यादा विकट हो सकता है। हालांकि बढ़ती बेरोजगारी के बीच तालिबान ने देश के लोगों को काम के बदले गेंहू देने का ऑफर दिया है। तालिबान ने भले ही लोगों को राहत देने के लिए ये स्कीम शुरू की है। लेकिन देश इतने बुरे हालातों में फंसा हुआ है कि इस प्रयास को बेहद कम माना जा रहा है। तालिबानी हुकूमत की इस योजना के तहत काबुल में दो महीने में करीब 11,600 टन गेहूं का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा हेरात, जलालाबाद, कंधार, मजार-ए-शरीफ और पोल-ए-खोमरी सहित देश के बाकी शहरों में 55,000 टन गेहूं वितरित किए जाने की योजना है। इस योजना के तहत सूखे से निपटने के इंतजाम किए जाएंगे। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, तालिबान की अंतरिम सरकार ने लोगों को श्रम के बदले गेहूं देने की घोषणा की है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। जिसके तहत लोगों को काम के बदले अनाज दिया जाएगा। मुजाहिद के मुताबिक ये कार्यक्रम देश के तकरीबन सभी बड़े शहरों में चलाया जाएगा। अकेले काबुल शहर में इसके तहत चालीस हजार लोगों को रोजगार मुहैया कराने की तैयारी है।

टीके की दोनों खुराक लेने वाले विदेशी यात्रियों के लिए सभी पाबंदियां हटाएगा अमेरिका

वाशिंगटन।अमेरिका, पूरी तरह से कोविड-19 रोधी टीका लगवाने वाले भारतीय नागरिकों समेत सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए आठ नवंबर से सारी पाबंदियां हटा लेगा, लेकिन यात्रियों को विमान में सवार होने से पहले कोरोना वायरस से संक्रमित न पाए जाने का सबूत दिखाना होगा। व्हाइट हाउस ने यह घोषणा की है। सोमवार को जारी ताजा यात्रा दिशा निर्देशों में जांच के बारे में नए प्रोटोकॉल भी शामिल हैं। सुरक्षा मजबूत करने के लिए टीका न लगवाने वाले यात्री चाहे अमेरिकी नागरिक, कानूनी स्थायी निवासी (एलपीआर) हों या बिना टीका लगवाने वाले विदेशी नागरिकों की छोटी-सी संख्या वाले लोग हों, उन्हें प्रस्थान करने के एक दिन के भीतर जांच करानी होगी। प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पत्रकारों को बताया, ''इस नयी अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा व्यवस्था के तहत विदेशी नागरिकों को अमेरिका आने के लिए पूरी तरह टीका लगवाने की आवश्यकता है। नयी व्यवस्था में जांच की आवश्यकता होना, संपर्क में आए लोगों का पता लगाने की प्रणाली मजबूत होने के साथ ही मास्क लगाना भी शामिल है। देश में अमेरिकियों और अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की सुरक्षा बढ़ाने के लिए विज्ञान और जन स्वास्थ्य पर आधारित सख्त सुरक्षा नियम हैं।'' अधिकारी ने बताया कि आठ नवंबर से गैर-नागरिक, गैर-आव्रजक हवाई यात्रियों को अमेरिका आने के लिए टीके की पूरी तरह खुराक लेनी होगी और अमेरिका आने वाले विमान में सवार होने से पहले कोविड-19 टीकाकरण का सबूत देना होगा।

चीन के 11 शहरों में तेजी से फैला कोरोना संक्रमण, सरकार ने की लॉकडाउन की घोषणा

नई दिल्ली।जिस देश से कोरोना वायरस संक्रमण की उत्पत्ति हुई थी वहीं अब एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ रहा है। हम बात कर रहे है चीन की जहां, कोरोना महामारी ने दुनिया के कई देशों में भी हाहाकार मचा कर रख दिया था। भारत में भी कोरोना महामारी से कई लोगों ने अपनों को खोया। हालांकि, इस समय कई देशों में कोरोना के मामले कम है लेकिन चीन में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी आने के बाद तहलका मच गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चीन ने कई शहरों में लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दी हैं। बता दें कि, चीन की राजधानी बीजिंग में अब तक कोरोना के 12 मामले सामने आ गए है। वहीं, चीन के अन्य शहरों मे कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब चीन सरकार लोगों को घरों से निकलने में पांबदी लगा चुकी है। सरकार के मुताबिक, चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नियमों में ढिलाई बर्दाशत नहीं किया जा सकता है। वहीं, चीन के इनर मंगोली में 150 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक कोरोना संक्रमण चीन के 11 शहरों में फैल चुका है।

कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाए बिना घर से निकलने में रोक

सरकार ने कोरोना के नियमों को सख्त करते हुए चीन की राजधानी बीजिंग में लोगों को घर से बाहर निकलने और काम पर जाने के लिए नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने के निर्देश दिए है। वहीं, अगर किसी की तबीयत खराब है तो उन्हें घर से निकलने की मनाही होगी। सरकार ने निर्देश लागू करते हुए कहा कि, अगर किसी ने भी इन नियमों को अनदेखा किया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रो तेइ-वू का 88 वर्ष के उम्र में निधन

सियोल। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रो तेइ-वू का निधन हो गया है। वह 88 वर्ष के थे। सियोल के एक अस्पताल ने यह जानकारी दी है। सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल ने बताया कि रो का एक बीमारी के इलाज के दौरान मंगलवार को निधन हो गया। उसने और कोई जानकारी नहीं दी। रो ने 1979 के सैन्य तख्तापलट के समर्थन में सियोल में एक सैन्य संभाग का नेतृत्व किया था जिससे सेना में उनके मित्र चुन डू-ह्वान राष्ट्रपति बने। तख्तापलट और उसके बाद 1980 में लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनकारियों पर सेना की कार्रवाई दक्षिण कोरिया के आधुनिक इतिहास के दो काले अध्याय हैं। इसके बाद 1987 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन तेज होने पर रोह और चुन को राष्ट्रपति चुनाव के लिए मंजूरी देनी पड़ी।

अफगानिस्तान में किस तरह जातीय और धार्मिक विभाजन अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा भड़का रहा है

नई दिल्ली (एजेंसी)।

अफगानिस्तान में अक्टूबर 2021 में मस्जिदों पर हुए हमलों में करीब सौ अफगान शिया मुसलमान मारे गए। ऐसा ही एक हमला 15 अक्टूबर को हुआ था, जब आत्मघाती हमलावरों के एक समूह ने कंधार में एक मस्जिद में विस्फोट किया था।इससे ठीक एक हफ्ते पहले, उत्तरी अफगानिस्तान में एक और आत्मघाती हमले में कम से कम 46 लोग मारे गए थे। इस्लामिक स्टेट समूह ने दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली। जातीयता और धर्म आज के अफगानिस्तान की राजनीति और संघर्षों को समझने की कुंजी हैं। अफगान मामलों पर मेरा शोध बता सकता है कि कैसे उन्होंने 1978 के बाद से अफगानिस्तान की राजनीति को प्रभावित करने वाली त्रुटियां पैदा कर दी हैं। अफगानिस्तान में सबसे बड़ा जातीय समूह सुन्नी मुस्लिम पश्तूनों का है जिसकी आबादी लगभग 45 प्रतिशत है और यह ज्यादातर देश के दक्षिण और पूर्व में केंद्रित हैं। पश्तून आबादी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, डूरंड रेखा के बीच की सीमा से आधे में विभाजित है, और दोनों देशों में राज्य के अधिकार तथा आधिकारिक सीमाओं की वैधता को चुनौती देने का एक लंबा इतिहास है।

कुछ समय पहले तक, जब पाकिस्तान ने सीमा पर बाड़ लगाई तो पश्तून आदिवासियों और लड़ाकों ने इस तरह सीमा पार की जैसे कि उसका कोई अस्तित्व ही न हो। पश्तूनों को अक्सर उनकी भूमि, सम्मान, परंपराओं और विश्वास के लिए बेहद स्वतंत्र और सुरक्षात्मक होने के रूप में वर्णित किया जाता है। पश्तून सेनानियों ने पहली बार एक हमलावर महाशक्ति को तब हराया था, जब उन्होंने 1838 से 1942 तक चले प्रथम एंग्लो-अफगान युद्ध के रूप में जाने जाने वाली लड़ाई में अफगानिस्तान को उपनिवेश बनाने के लिए भेजी गई एक ब्रिटिश सेना को परास्त कर दिया था। पश्तून कबीलों और कुलों के युद्ध कौशल ने उन्हें अफगानिस्तान की राजनीति में बहुत प्रभावशाली बना दिया है। दो अल्पकालिक अपवादों को छोड़कर, 1929 में और 1992 और 1994 के बीच, केवल पश्तून नेताओं ने ही 1750 से अफगानिस्तान पर शासन किया है। अफगानिस्तान में दूसरा सबसे बड़ा जातीय समूह ताजिक हैं। यह एक ऐसा शब्द है जो जातीय ताजिकों के साथ-साथ अन्य सुन्नी मुस्लिम फारसी भाषियों को भी संदर्भित करता है। ताजिक, जो अफगान आबादी का लगभग 30 प्रतिशत हैं और ज्यादातर उत्तर पूर्व तथा पश्चिम में केंद्रित हैं, उन्हें आमतौर पर पश्तूनों ने अफगानिस्तान में जीवन के ताने-बाने के हिस्से के रूप में स्वीकार किया है, शायद सुन्नी इस्लाम के उनके सामान्य पालन के कारण।

तीसरा सबसे बड़ा सुन्नी मुस्लिम समूह उज़्बेक हैं और ये देश के उत्तर में निकट से संबंधित तुर्कमेन हैं, जिनकी लगभग 10 प्रतिशत आबादी है। हजारा - अफगान आबादी का लगभग 15 प्रतिशत हैं जो पारंपरिक रूप से अफगानिस्तान के केंद्र में ऊबड़-खाबड़ पर्वतीय इलाके में रहते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें उन्होंने ऐतिहासिक रूप से पश्तून कबाइलियों से आश्रय मांगा था, जिन्होंने उनके इस्लाम के शिया संप्रदाय के पालन को अस्वीकार कर दिया था। हज़ारा ऐतिहासिक रूप से अफ़ग़ानिस्तान के सबसे गरीब और हाशिए पर रहे लोगों में शामिल रहे हैं। जब अप्रैल 1978 में अफगानिस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी के एक गुट ने सत्ता संभाली, तो अधिकांश अफगानों ने शायद ही कोई प्रतिक्रिया दी, क्योंकि अफगान सरकार ने पारंपरिक रूप से बड़े शहरों के बाहर बहुत सीमित भूमिका निभाई थी। हालाँकि, जब कम्युनिस्टों ने अपने कार्यकर्ताओं को अफगान बच्चों को मार्क्सवादी हठधर्मिता सिखाने के लिए रूढ़िवादी गाँवों में भेजा, तो उन्होंने अचानक विद्रोह कर दिया। जब 1979 में सोवियत संघ ने आक्रमण किया, तो प्रतिरोध अफगानिस्तान के अधिकांश हिस्सों में फैल गया। अपनी भूमि की रक्षा करने वाले, सभी जातीय समूहों के मुस्लिम योद्धा मुजाहिदीन लोगों ने सोवियत सेना का विरोध करने में भूमिका निभाई। बाद में, अब्दुल रशीद दोस्तम नामक एक कठोर उज़्बेक कम्युनिस्ट मिलिशिया नेता ने अधिकांश उज़्बेक मुजाहिदीन का सफाया कर दिया, और अधिकांश हज़ारा मुजाहिदीन दलों

ने शत्रुता को कम करने के लिए सोवियत संघ के साथ एक गुप्त समझौता किया।

हालाँकि, अधिकांश पश्तूनों और ताजिकों ने सोवियत संघ की वापसी और काबुल में सोवियत समर्थित शासन के पतन तक विरोध करना जारी रखा। सोवियत संघ ने अपने नियंत्रण वाले अफगानिस्तान के क्षेत्रों में अल्पसंख्यक हितों और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया, जिसका नतीजा बड़े शहरों के सांस्कृतिक रूप से विकसित होने के रूप में निकला। इससे शहर का जीवन अनेक ग्रामीण अफगानों के लिए अपरिचित रूप से विदेशी बन गया। फरवरी 1989 में सोवियत लाल सेना की वापसी के बाद मुजाहिदीन पार्टियों को अमेरिकी सहायता बंद हो गई, जिसने मुजाहिदीन के फील्ड कमांडरों को बदल दिया, जिनकी पार्टी के नेताओं के प्रति वफादारी सैन्य रूप से स्वतंत्र स्थानीय नेताओं में वित्तीय और सैन्य संसाधनों को वितरित करने की उनकी क्षमता पर आधारित थी। इसी तरह, अप्रैल 1992 में इसके पतन के बाद शासन की मिलिशिया और इकाइयाँ भी स्वतंत्र हो गईं। अफगानिस्तान, विशेष रूप से पश्तून क्षेत्र, खंडित हो गए, सैकड़ों स्थानीय नेताओं और सरदारों ने क्षेत्र, नशीली दवाओं के उत्पादन, तस्करी के मार्गों और आबादी कर लगाने के लिए लड़ाई लड़ी। जबकि कई स्थानीय नेताओं ने अपने परिजनों और रिश्तेदारों के कल्याण की परवाह की, कुछ ऐसे सरदार थे जिन्होंने साथी अफगानों के साथ दुर्व्यवहार किया।

ईरान में हुआ साइबर हमला, पूरे देश का पेट्रोल पंप हुआ ठप

दुबई। (एजेंसी)।

पूरे ईरान के ईंधन बिक्री केंद्र (पेट्रोल पंप) पर मंगलवार को उस समय काम ठप हो गया, जब ईंधन सब्सिडी की प्रणाली को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर में खराबी आ गई और बिक्री रोकनी पड़ी। ईरान की अर्द्धसरकारी समाचार एजेंसी ने इसे साइबर हमला करार दिया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिसमें तेहरान के ईंधन बिक्री केंद्रों पर कारों को अपनी बारी के लिए कतार में खड़े हुए देखा जा सकता है। सरकारी टीवी ने हालांकि, इसकी वजह नहीं बताई है लेकिन कहा कि तेल मंत्रालय के अधिकारी '' तकनीकी समस्या का समाधान निकालने के लिए आपात बैठक कर रहे हैं।'' अर्द्ध सरकारी समाचार एजेंसी ने घटना को साइबर हमला करार देते हुए कहा कि उसने देखा कि जो लोग सरकार द्वारा जारी कार्ड से ईंधन खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें 'साइबर हमला 64411' का संदेश मिल रहा है।

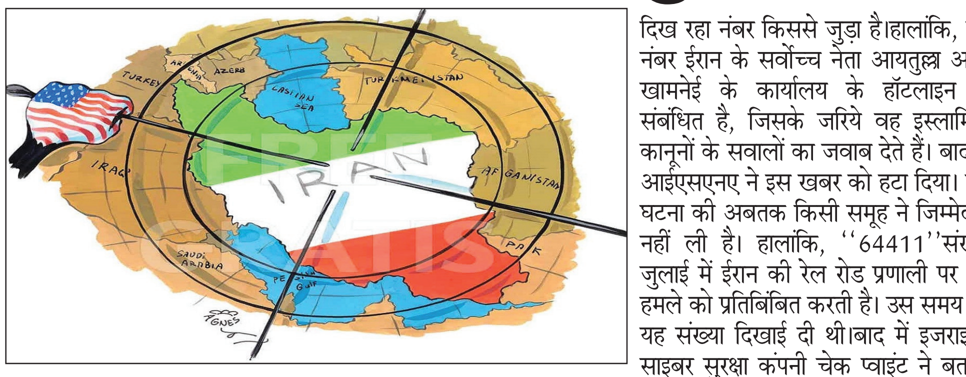

उल्लेखनीय है कि ईरान की अधिकतर जनता अपने वाहनों में ईंधन भरवाने के लिए सब्सिडी पर आश्रित है, खासतौर पर देश की खराब होती अर्थव्यवस्था की वजह से। आईएसएनए ने यह नहीं बताया कि संदेश में दिख रहा नंबर किससे जुड़ा है।हालांकि, यह नंबर ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के कार्यालय के हॉटलाइन से संबंधित है, जिसके जरिये वह इस्लामिक कानूनों के सवालों का जवाब देते हैं। बाद में आईएसएनए ने इस खबर को हटा दिया। इस घटना की अबतक किसी समूह ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि, ''64411''संख्या जुलाई में ईरान की रेल रोड प्रणाली पर हुए हमले को प्रतिबिंबित करती है। उस समय भी यह संख्या दिखाई दी थी।बाद में इजराइली साइबर सुरक्षा कंपनी चेक प्वाइंट ने बताया था कि ईरान की रेल प्रणाली पर हैकरों के एक समूह ने हमला किया था, जो स्वयं को हिंदू देवता के नाम पर 'इंद्र' कहते हैं। इससे पहले 'इंद्र' नाम के इस समूह ने सीरिया की कंपनियों को भी निशाना बनाया था, जहां ईरान के हस्तक्षेप से राष्ट्रपति पद पर बशर असद बने हुए हैं।

इस्लाम से सनातन की ओर इंडोनेशिया, पूर्व राष्ट्रपति की बेटी अपनाने जा रही हैं हिंदू धर्म

नई दिल्ली (एजेंसी)।

दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया में हिन्दू आबादी दो फीसदी से भी कम है। फिर भी वहां की हर चीज पर हिन्दू संस्कृति की छाप दिखती है। इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो का नाम भी महाभारत से प्रेरित है। लेकिन अब इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति की बेटी आज इस्लाम धर्म छोड़ने वाली हैं। बाली में सुकर्णो हेरीटेज एरिया में हिन्दू धर्म अपनाएंगी। सुकमावती हिन्दू धर्म की सभी परंपराओं से पूरी तरफ वाकिफ हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दादी से प्रभावित होकर सुकमावती हिन्दू धर्म अपनाएंगी। सुकमावती ने खुद कहा कि उन्हें हिन्दू धर्म की काफी जानकारी है।

ईशनिंदा के आरोप लगे थे

2018 में कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों ने उनके खिलाफ ईशनिंदा की शिकायत दर्ज कराई थी। सुकमावती के खिलाफ एक कविता शेयर किए जाने के बाद ये शिकायत दर्ज कराई गई थी। कट्टरपंथियों ने इस्लाम का अपमान किए जाने का आरोप लगाया। इसके बाद सुकमावती को माफी भी मांगनी पड़ी लेकिन विवाद ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कट्टरपंथी अकसर उन्हें निशाना बनाते रहे।

कौन हैं सुकमावती

सुकमावती अभी 70 साल की हैं और सुकर्णो की तीसरी बेटी हैं। उनसे छोटी पूर्व राष?ट्रपति मेगावती सुकर्णोपुत्री हैं। वह इंडोनेशिया नैशनल पार्टी की संस?थापक भी हैं। उन?होंने कांजेंग गुस?ती पानगेरान अदिपति आर्या से शादी की थी लेकिन वर्ष 1984 में उनका तलाक हो गया था।

परमाणु बम बनाने की ओर बढ़ रहा ईरान? इजरायल एयरफोर्स ने अटैक की शुरू की तैयारी

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

साल की शुरुआत में ही इजरायल डिफेंस फोर्स के चीफ ने तैयारियों के लिए अरबों डॉलर का फंड अलॉट किया। साल 2015 के अमेरिका से ईरान के परमाणु समझौते में वापसी के संकेतों के बाद से ही इजरायल अलर्ट हो गया था। बाइडेन एडमिनिट्रेशन एक बार फिर ईरान के साथ परमाणु समझौते में जुड़ना चाहता है। इजरायल एयरफोर्स जल्द ही ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक की तैयारी शुरू करेगा। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने ईरान के एटम बम के हमले के मद्देनजर ये तैयारियां शुरू की हैं।

इजरायल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार साल 2015 में अमेरिका और अन्य देशों के साथ जेसीपीओए पर हस्ताक्षर के बाद इज़रायल ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर सैन्य हमले के मुद्दे को बैक बर्नर पर रखा। लेकिन 2018 में अमेरिका की ट्रंप सरकार द्वारा इस डील से हाथ पीछे खींच लिए गए। लेकिन ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चीन और रूस इस समझौते को बचाने में लगे रहे।

ईरान ने क्रास की रेड लाइन

पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में इज़रायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान के परमाणु हथियार प्रोग्राम को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों को तोड़कर इसने 'रेड लाइन' का उल्लंघन किया है। लेकिन इजरायल तेहरान को परमाणु बम हासिल करने की मंजूरी नहीं देगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए अपने पहले भाषण में बेनेट ने दावा किया कि इस्लामिक रिपब्लिक ने हाल के सालों में अपनी परमाणु क्षमता और हथियार-ग्रेड यूरेनियम को समृद्ध करने की क्षमता में एक बड़ी छलांग लगाई है।

इमरान खान, शी चिनफिंग ने अफगानिस्तान में मानवीय, आर्थिक सहायता भेजने की अपील की

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने मंगलवार को पहली बार संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि तालिबान शासित अफगानिस्तान को तुरंत मानवीय एवं आर्थिक सहयोग मुहैया कराएं, जहां सर्दियों से पहले आवश्यक सामान की काफी किल्लत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री खान की राष्ट्रपति शी के साथ टेलीफोन पर हुई वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की।

इसने कहा, ''दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि अफगानिस्तान के लोगों को तुरंत मानवीय एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराएं ताकि उनकी दिक्कतें दूर हो सकें, अस्थायित्व रूके और देश के पुनर्निर्माण में मदद मिले।'' कतर में एक उच्चस्तरीय बैठक में तालिबान के प्रतिनिधियों के

साथ चीन के विदेश मंत्री वांग यी की मुलाकात के एक दिन बाद दोनों नेताओं ने फोन पर बात की। चीन ने सितंबर में 3.1 करोड़ डॉलर की मदद दी थी, जिसमें युद्धग्रस्त राष्ट्र को खाद्य पदार्थों एवं स्वास्थ्य सामग्री की आपूर्ति शामिल है। इसी तरह पाकिस्तान ने पड़ोसी देश को खाद्य तेल और दवाएं भेजी थीं।

पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने की शी चिनफिंग से फोन पर बात, जानिए क्या हुई बात

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग मंगलवार को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने पर सहमत हुए, जिनमें आर्थिक बाधा को दूर करने के लिए मुक्त व्यापार समझौते के दूसरे चरण द्वारा पेश की गई संभावनाओं को मूर्त रूप देना भी शामिल है। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा यहां जारी बयान में बताया गया कि प्रधानमंत्री खान और राष्ट्रपति चिनफिंग के बीच फोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग की समीक्षा की। बयान के मुताबिक, इस दौरान खान ने चीन के कोविड-19 पर सफलतापूर्वक काबू पाने के अलावा पाकिस्तान के साथ टीका सहयोग समेत विकासशील देशों को राहत पहुंचाने के लिये उसकी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा, '' कोविड-19 की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़े नकारात्मक असर को देखते हुए दोनों नेता द्विपक्षीय आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को मजबूत करने पर सहमत हुए, जिनमें चीन-पाकिस्तान मुक्त व्यापार समझौते के दूसरे चरण द्वारा पेश की गई संभावना को पूर्ण रूप से मूर्त रूप देना शामिल है, ताकि आर्थिक बाधाओं से निकला जा सके।''

बयान के मुताबिक, बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने समय से और उच्च गुणवत्तापूर्ण तरीके से चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना (सीपीईसी) को लागू करने की प्रशंसा की और सीईपीसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में चीनी निवेश का स्वागत किया। उन्होंने जोर दिया कि यथाशीघ्र एमएल-1 रेल परियोजना को लागू करने से पाकिस्तान के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय विकास का भू आर्थिक दृष्टिकोण मजबूत होगा। गौरतलब है कि महत्वकांक्षी सीईपीसी परियोजना की शुरुआत वर्ष 2015 में चीनी राष्ट्रपति चिनफिंग की पाकिस्तान यात्रा के दौरान शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य पश्चिमी चीन को दक्षिण-पश्चिम पाकिस्तान स्थित समुद्री बंदरगाह को सड़क और रेल मार्ग से जोड़ना और अन्य आधारभूत संरचनाओं का विकास करना है। इमरान खान ने वार्ता के दौरान जलवायु परिवर्तन रोकने में चीन के नेतृत्व की भूमिका को स्वीकार किया और चिनफिंग को इस संबंध में पाकिस्तान द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। बयान के मुताबिक, फोन पर हुई दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान अफगानिस्तान पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने विश्व समुदाय से अफगानिस्तान को तत्काल मानवीय और आर्थिक सहायता देने का आह्वान करते हुए युद्धग्रस्त देश के पुनर्निर्माण कार्य से जुड़े रहने पर जोर दिया।

केजरीवाल पर सीएम योगी ने साधा निशाना,

पहले भगवान श्रीराम को गाली देते थे, आज मत्था टेक रहे

लखनऊ। आगामी चुनावों के मद्देनजर तमाम दल राम नाम के सहारे अपनी राजनीतिक नैया पार लगाने की कोशिश में हैं। वहीं अब इसमें आम आदमी पार्टी **(Aam Aadmi Party)** भी सवार होती दिख रही है। ऐसे में इशारों-इशारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ **(Chief Minister Yogi Adityanath)** ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल से कोरोना काल में एक छोटा सा राज्य नहीं संभला और चुनावी मौसम में उन्हें राम की याद आई है।बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मलेन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कोरोना काल में दिल्ली में रह रहे यूपी के लोगों को भगाया गया। छोटी सी दिल्ली को संभाल नहीं पाए। अब जब चुनाव नजदीक है तो उन्हें राम याद आ रहे हैं। ये सपा-बसपा-कांग्रेस और अब एक दिल्ली वाले भी पहले भगवान श्री राम को गाली देते थे और अब माथा टेकने अयोध्या जा रहे हैं। योगी ने कहा कि क्या इस प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस को शासन करने का मौका नहीं मिला था? क्या उनकी जिम्मेदारी प्रदेश के प्रति नहीं थी? एक दिल्ली वाले हैं जो आज कह रहे हैं कि आज ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे। जब मौका मिला था तो यूपी-बिहार वालों को दिल्ली से भगा दिया, जब अवसर मिला तो जिम्मेदारी नहीं मिली। पहले प्रभु श्रीराम को गाली देते थे। आज जब लग रहा है कि प्रभु श्रीराम के बिना नैया पार नहीं होगी तो मत्था टेकने आ रहे हैं। अच्छी बात है। राम के महत्व को अस्तित्व को कम से कम स्वीकार तो किया। अन्यथा विपक्षी दलों का कोई ऐसा नेता नहीं, जिसने स्वर्गीय बाबूजी (कल्याण सिंह) को कटघरे में खड़ा न किया हो।

केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया योगी के पलटवार का जवाब

वहीं सीएम योगी के हमले के बाद अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि दिल्ली मतलब सबको मुफ्त दवाई, बेहतर शिक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बुजुर्गों का सम्मान आज मैंने एलान किया कि दिल्ली के लोगों को कल से अयोध्या तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे। फिर इसे **UP** में भी लागू करेंगे। इस योजना से करोड़ों जनता प्रभु के दर्शन कर पाएगी। योगीजी, इसमें आपको आपत्ति क्यों?

नौकरशाह के जन्म प्रमाण पत्र की तलाश करने वाले नबाव मालिक कौन होते हैं : यास्मीन

मुंबई । फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को क्रूज से पकड़ने वाले नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट ट्वीट कर उनका नाम 'समीर दाऊद वानखेड़े' बताया था।इसके बाद मंगलवार को वानखेड़े की बहन यास्मीन ने मलिक पर पलटवार किया है। वानखेड़े की बहन ने कहा, एक नौकरशाह के जन्म प्रमाण पत्र की तलाश करने वाला वह (नवाब मलिक) कौन होता है? उसकी रिसर्च टीम ने दुबई से बॉम्बे तक तस्वीर को पोस्ट किया है। हमें मौत की धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे भी हर रोज झूठे सबूत पेश करने चाहिए।इसके पहले नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े ने भी पलटवार कर कहा था कि वह एक हिंदू पिता और मुस्लिम मां के बेटे हैं।वानखेड़े ने कहा कि उनपर लगाए गए आरोप न सिर्फ अपमानजनक हैं बल्कि यह उनके परिवार की निजता पर हमला है। समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे हैं।उनपर ये आरोप क्रूज पर मौजूद गवाह की तरफ से लगाए गए हैं। किरण गोसावी के बॉडीगार्ड रहे प्रभाकर सैल ने आरोप लगाकर कहा कि शाहरुख के बेटे को छोड़ने के एवज में 25 करोड़ रुपये रिश्वत की बात उन्होंने सुनी थी।हालांकि, आखिर में डील 18 करोड़ पर फाइनल हुई थी, जिसमें से आठ करोड़ रुपये समीर वानखेड़े को मिलने थे। किरण गोसावी वहीं शख्स है, जिसकी आर्यन खान के साथ ली गई एक सेल्फी वायरल हुई थी। वहीं, वानखेड़े ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों और मानहानिकारक आक्षेपों का स्पष्ट रूप से खंडन किया है। उन्होंने इस झूठा, भ्रामक, शरारती और दुर्भावनापूर्ण आरोप बताया है। वानखेड़े ने कहा,'मुझे व्यक्तिगत रूप से एक जाने-माने राजनीतिक व्यक्ति द्वारा टारगेट किया गया। इसका एकमात्र मकसद जो मैं समझ सकता हूं वह यह है कि उनके एक रिश्तेदार समीर खान को एनडीपीएस मामले में कानून के अनुसार गिरफ्तार हुआ और बाद में अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया था। उस समय से मुझ पर और मेरे परिवार के सदस्यों पर लगातार व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं।'

म्यांमा से आए शरणार्थियों के 1900 से अधिक बच्चों को सरकारी स्कूल में दिया गया एडमिशन

(एजेंसी)

म्यांमा में बिगड़े हालात के चलते अपने परिवारों के साथ मिजोरम में शरण लेने वाले 1,900 से अधिक बच्चों को राज्य के विभिन्न सरकारी स्कूलों में दाखिल दिया गया है जहां वे निशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। शिक्षा विभाग के निदेशक जेम्स ललरिंचाना ने कहा कि राज्य सरकार अगस्त से ही म्यांमा के शरणार्थी बच्चों का स्कूल में प्रवेश दे रही है। उन्होंने कि यह पहल पूरी तरह से मानवीय आधार पर शुरू की गई है। म्यांमा के चिन राज्य के साथ मिजोरम की 510 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। म्यांमा में फरवरी में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद से वहां के नागरिक अन्य जगहों पर शरण ले रहे हैं। जेम्स ने कहा, '' हम म्यांमा के प्रवासी नेताओं के अनुरोध को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यदि मानवीय संकट के कारण पलायन करने वाले शरणार्थियों को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है, तो हमें अंतरराष्ट्रीय समुदाय की तरफ से भी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है।'' उन्होंने बताया कि अब तक कुल 1,972 शरणार्थी बच्चों को स्कूलों में दाखिला किया गया है जो वर्तमान में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

शाह ने पुलवामा के सीआरपीएफ कैंप में बिताई रात, आतंकी हमले में शहीद 40 जवानों को दी श्रद्धांजलि

श्रीनगर ।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार सुबह 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए 40 सीआरपीएफ जवानों को श्रद्धांजलि दी। शाह ने सोमवार को पुलवामा जिले में शहीद स्मारक पर सीआरपीएफ जवानों के साथ रात बिताने के लिए जम्मू-कश्मीर के अपने तीन दिवसीय दौरे को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। सूत्रों ने बताया कि अमित शाह इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, सीआरपीएफ के डीजी और सचिव सहित दिल्ली से पूरे शीर्ष अधिकारियों के अमले के साथ जम्मू-कश्मीर पहुंचे हैं। अमित शाह ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया पुलवामा के कायराना आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के बहादुर जवानों को आज पुलवामा शहीद स्मारक पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश की रक्षा हेतु आपका समर्पण व सर्वोच्च बलिदान आतंकवाद के समूल नाश के हमारे संकल्प को और दृढ़ करता है। वीर बलिदानियों को कोटि-कोटि वंदन। उन्होंने ट्विटर पर लिखा- पुलवामा के शहीद स्मारक पर हमारे वीर बलिदानियों की स्मृति में पौधारोपण किया। इससे पहले शाह सोमवार को कहा था कि वह अर्धसैनिक बलों के जवानों के साथ समय बिताना चाहता था। वह सोमवार रात सीआरपीएफ कैंप में ही रुके थे।

सोशल मीडिया पर उठी ऑनलाइन परीक्षा की मांग, बोर्ड ने विद्यार्थियो को दी ये छूट

नई दिल्ली (एजेंसी)।

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) ने 18 अक्टूबर को कक्षा 10वीं और 12वीं के टर्म-1 एग्जाम की तारीखों जारी कर दिया है। साथ ही सीबीएसई ने आदेश जारी करते हुए परीक्षा की तारीखों की भी घोषणा कर दी है। आदेश में कहा गया है कि कक्षा 10वीं के टर्म-1 एग्जाम 30 नवंबर से शुरू होंगे, जबकि 12वीं कक्षा के 1 दिसंबर से शुरू होंगे। वहीं, ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में लिए जाएंगे। सीबीएसई के इस फैसले से विद्यार्थी नाराज़ हैं और सोशल मीडिया पर इसका विरोध जता रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में परीक्षा करवाने की मांग कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि सीबीएसई बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहा है। कोरोना महामारी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। हालांकि, सीबीएसई ने साफ किया है कि एग्जाम ऑफलाइन मोड में ही होंगे। साथ ही बोर्ड ने सुनिश्चित किया कि एग्जाम में कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सभी तरह की सावधानियां बरती जाएंगी। सीबीएसई ने एक नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने उन स्टूडेंट्स को राहत दी है जो अपने शहर से बाहर हैं। नोटिस में कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा के वे छात्र जो वर्तमान में उस शहर में नहीं हैं जहां वे नामांकित हैं, ऐसे में वे अपना शहर और परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। इसके लिए उन्हें अपने स्कूल से अनुरोध करना होगा। सीबीएसई बोर्ड जल्द ही स्टूडेंट्स को सूचित करेगा कि वह कब से अपने स्कूल में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सीबीएसई ने कहा है कि विद्यार्थी और स्कूल नियमित तौर पर सीबीएसई वेबसाइट चेक करते रहें। आवेदन के लिए विद्यार्थियों को कुछ ही दिनों का समय मिलेगा। अंतिम तिथि के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

शिवसेना का तंज, भाजपा अपने को केंद्रीय जांच एजेंसिया की आका मान रही

मुंबई ।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के क्रूज जहाज पर नशीले पदार्थ पकड़ने के मामले पर जारी राजनीतिक घमासान के बीच शिवसेना ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ऐसा मानकर चल रही है कि केंद्रीय जांच एजेंसिया की आका वहीं है, लेकिन भाजपा को नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र में आका बदलते रहते हैं। शिवसेना के मुखपत्र 'सामना में प्रकाशित संपादकीय में कहा गया है कि नशीले पदार्थ मामले में 25 करोड़ रुपये मांगे जाने के आरोप एक बड़ी समस्या का केवल छोटा-सा हिस्सा है।मामले में बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख का बेटा आर्यन खान आरोपी है। सामना में कहा गया, आका और उनके सियासी हुक्म सुनने वालों को परिणामों की चिंता करनी चाहिए। सवाल अभिनेता शाहरुख खान या उनके बेटे का नहीं है बल्कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के चरित्र और ईमानदारी का है। इसकी जांच कौन करेगा कि मामले में एनसीबी का गवाह किरण गोसावी कहां छिपा है? पुणे में धोखाधड़ी के मामले का सामना कर रहा गोसावी तब से लापता है, जब से मुंबई तट पर महीने एक क्रूज जहाज पर एनसीबी के छापा मारने के बाद आर्यन खान के साथ उसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।गोसावी ने उसके सहायक और मामले में एक और गवाह प्रभाकर सैल द्वारा वसूल की दावों से इनकार कर कहा कि वह जल्द ही लखनऊ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा। एनसीबी ने आर्यन को छोड़ने के बदले में एजेंसी के मुंबई मंडल के निदेशक समीर वानखेड़े सहित कुछ अधिकारियों द्वारा 25 करोड़ रुपये की वसूली मांगने के सैल के दावों की जांच के आदेश दिए हैं। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ तीन दलों शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाया है कि विपक्षी दलों को निशाना बनने के लिए केंद्रीय एजेंसियां का इस्तेमाल किया जा रहा है। 'सामना' में संपादकीय में कहा गया है, ''भाजपा ऐसा मानकर चल रही है कि वह केंद्रीय जांच एजेंसियों का आका है। उसे यह भूलना नहीं चाहिए कि लोकतंत्र में आका बदलते रहते हैं। इतिहास इसका गवाह है। शिवसेना ने दावा किया, ''भाजपा किसी वक्त सिद्धांतों, त्याग और राष्ट्रवाद को मानने वाली पार्टी थी लेकिन हम उसके मौजूदा रूप में उससे इसकी उम्मीद नहीं रख सकते हैं। यहां तक कि भाजपा में वरिष्ठ नेता भी असहज हैं।'' उसने कहा कि लोग इसपर हैरान हैं कि कुछ ग्राम नशीले पदार्थ के लिए आर्यन खान मामले में 25 करोड़ रुपये क्यों मांगे गए।

आग से 4 लोगों की मौत के बाद एक पल में उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार

नई दिल्ली (एजेंसी)।

दिल्ली के ओल्ड सीमापुरी इलाके में मंगलवार सुबह एक मकान में आग लगने से एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई। मृतकों में पति-पत्नी और बेटी-बेटा शामिल हैं। एक साथ चार मौतों से हंसता-खेलता पूरा परिवार एक पल में उजड़ गया। हालांकि, हादसे में परिवार का एक बेटा सकुशल बच गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह घटना तब हुई जब ये लोग सो रहे थे। मृतकों की पहचान होरीलाल (59), उसकी पत्नी रीना (55), बेटा आशु (24) और बेटी रोहिणी (18) के रूप में हुई है। परिवार के सदस्य मकान की तीसरी मंजिल पर सो रहे थे, जबकि उनका 22 वर्षीय बेटा अक्षय बाल-बाल बच गया क्योंकि वह दूसरी मंजिल पर सो रहा था। पुलिस ने सभी चारों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। डीसीपी (शाहदरा) आर. सत्यसुंदरम ने बताया कि हमारी पुलिस टीम और दमकल कर्मी तुरंत घटनास्थल पहुंचे और आग पर काबू पाया। हादसे में चार लोगों की मौत की खबर मिलते ही क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस लैब के अधिकारी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने बताया कि आग मकान की तीसरी मंजिल में लगी और फिर फैल गई होगी।

उम्मीद है कि परिवार के इन सदस्यों की मौत फेफड़ों में धुआं भर जाने के कारण हुई होगी, लेकिन केवल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ही मौत की असली वजह का पता चल पाएगा। पुलिस ने बताया कि परिवार में बचा एकमात्र सदस्य अक्षय सफियाबाद में मजदूरी करता है। वह काम के बाद देर रात करीब दो बजे घर आया था। वह खाना लेने तीसरी मंजिल पर गया और बाद में दूसरी मंजिल पर आकर सो गया।

वह बच गया क्योंकि आग तीसरी मंजिल से आगे नहीं फैली। उन्होंने बताया कि होरीलाल शास्त्री भवन, दिल्ली में सहायक के तौर पर काम करता है और उसे मार्च 2022 में रिटायर होना था। उसकी पत्नी नगर निगम में सफाईकर्मी के तौर पर काम करती थी। उसकी बेटी एक सरकारी स्कूल में 12वीं कक्षा में पढ़ती थी, जबकि बेटा बेरोजगार था। दिल्ली फायर सर्विस अतुल गर्ग ने बताया कि आग लगने के बारे में मंगलवार सुबह करीब चार बजे सूचना मिली और दमकल की चार गाड़ियों को तुरंत घटनास्थल पर भेजा गया।

समलैंगिक जोड़े को अपने फेम क्रीम ब्लीच के विज्ञापन अभियान में त्योहार मनाते हुए दिखाया गया

डाबर ने समलैंगिक कपल वाले करवा चौथ के विज्ञापन के लिए मांगी माफी

(एजेंसी)।

घरेलू एफएमसीजी कंपनी डाबर ने करवा चौथ पर अपना विज्ञापन वापस ले लिया है जिसमें एक समलैंगिक जोड़े को अपने फेम क्रीम ब्लीच के विज्ञापन अभियान में त्योहार मनाते हुए दिखाया गया है। कंपनी ने इसके लिए बिना शर्त माफी मांगी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और सत्तारूढ़ भाजपा के एक नेता की प्रतिक्रिया के बाद कंपनी ने विज्ञापन अभियान वापस ले लिया है। डाबर इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा, ''फेम का करवा चौथ अभियान सभी सोशल मीडिया हैंडल से वापस ले लिया गया है और अनजाने में लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। इस घटना से एक सप्ताह पहले पारंपरिक परिधान निर्माता फैबइंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दक्षिणपंथी समूहों के विरोध के बाद अपनी नई उत्सव लाइन के बारे में एक प्रचार सामग्री को हटाया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले फेम क्रेम विज्ञापन, में दो युवतियों को अपने पहले करवा चौथ उत्सव की तैयारी करते हुए दिखाया गया है, जबकि उसमें से एक दूसरे के चेहरे पर ब्लीच लगा रही है। विज्ञापन में दोनों महिलाएं करवा चौथ के महत्व और इसे मनाने की वजह पर चर्चा करती नजर आ रही हैं। एक अन्य महिला उनके साथ आती है और उन दोनों को इस अवसर पर पहनने के लिए एक साड़ी उपहार में देती है। रात में, दोनों महिलाएं पति-पत्नी की तरह एक-दूसरे का सामना करती हुई दिखाई देती हैं। जहां एक थाली में पानी का एक गिलास हैं। इसमें दोनों महिलाओं को पार्टनर के रूप में दर्शाया गया है, जिसके बाद स्क्रीन पर फेम का लोगो दिखाई देता है और वॉयसओवर कहता है, 'ग्लो विथ प्राइड%। हालांकि, जनता के एक हिस्से ने डाबर के इस रुख के लिए उसकी सराहना भी की। सोमवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि उन्होंने राज्य के पुलिस प्रमुख को डाबर इंडिया को 'आपत्तिजनक सौंदर्य उत्पाद विज्ञापन को वापस लेने और उपभोक्ता सामान निर्माता द्वारा विज्ञापन वापस नहीं लेने पर कानूनी कदम उठाने का निर्देश दिया है। इससे पहले रविवार रात को डाबर ने एक अलग बयान में सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, ÷डाबर और फेम एक ब्रांड के रूप में विविधता, समावेश और समानता के लिए प्रयास करते हैं, और हम अपने संगठन और अपने समुदायों के भीतर इन मूल्यों का गर्व से समर्थन करते हैं। बयान में कहा गया है, ÷हमारे अभियान भी यही दर्शाते हैं। हम समझते हैं कि हर कोई हमारे रुख से सहमत नहीं होगा, और हम एक अलग दृष्टिकोण रखने के उनके अधिकार का सम्मान करते हैं। हमारा इरादा किसी भी विश्वास, रीति-रिवाजों और परंपराओं, धार्मिक या किसी भाव को ठेस पहुंचाना नहीं है।

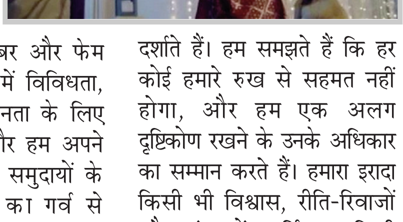

संक्षिप्त समाचार

रोहिंग्याओं को वापस भेजने की कोई योजना नहीं, कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

बेंगलुरु । कर्नाटक सरकार ने साफ कर दिया है कि राजधानी बेंगलुरु में रह रहे रोहिंग्याओं को वापस भेजने की कोई योजना नहीं है। यह जानकारी राज्य सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को दी। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि ऐसे 72 रोहिंग्याओं की पहचान की गई है, जो शहर में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। शीर्ष अदालत में एक साल के भीतर रोहिंग्याओं की पहचान करने, उन्हें हिरासत में लेने और निर्वासित करने को लेकर याचिका दायर हुई थी। अदालत में दिए हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि बेंगलुरु सिटी पुलिस ने अपने अधिकार क्षेत्र में रोहिंग्याओं को किसी कैंप या डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा है। हालांकि, बेंगलुरु शहर में 72 रोहिंग्याओं की पहचान हुई है, जो अलग-अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। बेंगलुरु सिटी पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई अब तक नहीं की है। उन्हें निर्वासित करने की तत्काल कोई योजना नहीं बनाई गई है। राज्य सरकार ने रोहिंग्या समुदाय के 72 लोगों की सूची भी अदालत को दी है और एड्वोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने की मांग की है। इन नामों में कई की उम्र 12 साल से कम है। अगस्त 2017 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद को बताया था राज्यों को रोहिंग्याओं समेत अवैध प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद रोहिंगा समुदाय के दो लोगों ने निर्वासन के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

भारत पर बुरा असर पिछले साल 6535 अरब रुपये का नुकसान

नई दिल्ली । विश्व मौसम संगठन की एक नई रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल चक्रवात, बाढ़ और सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भारत को 6535 अरब रुपये का नुकसान हुआ है। चीन को सबसे अधिक 238 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। नुकसान के मामले में भारत 87 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान और जापान 83 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले साल एशिया ने रिकॉर्ड गर्मी देखी है। एशिया का औसत तापमान 1981-2010 की तुलना में 1.39 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। दक्षिण और पूर्व एशिया में मानसून के असामान्य रूप से सक्रिय रहने के कारण कई देशों में भयंकर नुकसान हुआ है। अम्फान जैसे तूफान की वजह से भारत में 24 लाख और बांग्लादेश में 25 लाख विस्थापित होने को मजबूर हुए। चक्रवात, मानसून की बारिश और बाढ़ ने दक्षिण एशिया और पूर्वी एशिया में घनी आबादी वाले क्षेत्रों को प्रभावित किया है। पिछले साल भारत, चीन, बांग्लादेश, जापान, पाकिस्तान, नेपाल और वियतनाम में लाखों लोगों का विस्थापन हुआ है। डब्ल्यूएमओ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी बताया है कि एशिया में और उसके आसपास समुद्र की सतह का तापमान वैश्विक औसत से तीन गुना अधिक बढ़ रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खाद्य सुरक्षा और पोषण पर प्रगति भी धीमी हो गई है। पिछले साल दक्षिण पूर्व एशिया में 48.8 मिलियन, दक्षिण एशिया में 305.7 मिलियन और पश्चिम एशिया में 42.3 मिलियन लोगों के कुपोषित होने का अनुमान है।

पार्टी मीटिंग में सोनिया गांधी का बीजेपी पर हमला

नई दिल्ली। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में महासचिवों, राज्य प्रभारियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के प्रदर्शन से लेकर जमीनी स्तर तक कांग्रेस के संदेश पर बात की। इसी के साथ ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर भी हमला किया। उन्होंने पार्टी मीटिंग में कहा कि हमें लोगों के सामने बीजेपी के झूठों का पर्दा फाश करना होगा। सोनिया गांधी ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) की बैठक में अनुशासन और एकता बनाए रखने पर जोर देते हुए कहा कि संगठन को मजबूत करने की भावना निजी महत्वाकांक्षाओं से ऊपर होनी चाहिए । उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए लड़ाई कार्यकर्ताओं को मिथ्या प्रचार की पहचान करने और उससे मुकाबले के लिए तैयार करने के साथ शुरू होती है। अपनी बैठक में बीजेपी पर हमला करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, हमें वैचारिक रूप से बीजेपी/आरएसएस के अभियान से लड़ना चाहिए। अगर हमें यह लड़ाई जीतनी है तो हमें दृढ़ विश्वास के साथ ऐसा करना होगा और हमें लोगों के सामने उनके झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए÷ उन्होंने कहा कि सरकार की ज्यादतियों के शिकार लोगों के लिए लड़ाई और तेज करनी चाहिए। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस का संदेश जमीनी स्तर तक नहीं पहुंच रहा है, मुझे नीतिगत मुद्दों पर राज्य के नेताओं के बीच स्पष्टता, सामंजस्य की कमी दिखती है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा देने का दिया निर्देश

नई दिल्ली । लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को घटना के गवाहों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि गवाहों के बयान तेजी से दर्ज किए जाएं। कोर्ट ने यूपी सरकार से लखीमपुर हिंसा में पत्रकार रमन कश्यप और एक श्याम सुंदर की हत्या की जांच पर जवाब दाखिल करने को भी कहा है। अब मामले की अगली सुनवाई आठ नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि घटना के दौरान 4-5 हजार लोगों की भीड़ थी जो सभी स्थानीय लोग हैं और यहां तक कि घटना के बाद भी ज्यादातर आंदोलन करते रहे। हमें यही बताया गया है। फिर, इन लोगों की पहचान में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोगों ने कार और कार के अंदर मौजूद लोगों को देखा है।लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को अब तक हुई कार्रवाई का ब्यौरा दिया। यूपी सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा, 30 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो चुके हैं। उनमें 23 प्रत्यक्षदर्शी गवाह हैं। कुछ ही लोग दूसरे राज्य के थे।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर,सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)

क्रांति समय
Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

सीबीआई ने नौसेना के अधिकारी समेत पांच लोगों को किया गिरफ्तार, खुफिया सूचनाएं लीक करने का आरोप

नेशनल डेस्क :

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने जासूसी के आरोप में नौसेना के एक अधिकारी समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक, 'सीबीआई ने कमांडर रैंक के नौसेना अधिकारी के अलावा दो पूर्व अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया है। इन अधिकारियों पर नौसेना से जुड़ी खुफिया सूचनाएं लीक करने का आरोप है। सभी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है।

हिमाचल के मनाली में 4.3 तीव्रता का भूकंप, पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ा एवलांच का खतरा

मनाली ।

हिमाचल प्रदेश के मशहूर पर्यटन स्थल मनाली में सुबह भूकंप का तेज झटके से धरती में कंपन महसूस हुआ। मंगलवार तड़के भूकंप के झटके से लोग सहम गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। भूकंप की तीव्रता काफी तेज थी, इस कारण अधिकतर लोगों ने झटके महसूस किए। लाहुल-स्पीति व मंडी में भी झटके महसूस किए गए। अभी तक नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। एसडीएम मनाली डाक्टर सुरेंद्र ठाकुर का कहना है फिलहाल भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। लेकिन फील्ड स्टाफ को अलर्ट किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में पता करें कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। प्रदेश में दो दिन के भीतर तीसरी बार हिमाचल की धरती हिली है। सोमवार को शिमला और इससे पहले चंबा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। लाहुल स्पीति में भी भूकंप के झटके महसूस होने से खतरा बढ़ गया है। यहां हिमस्खलन होने की आशंका बढ़ गई है। हाल ही में लाहुल स्पीति में दो से तीन फीट तक हिमपात हुआ है। वहीं, पहाड़ियों पर इससे भी ज्यादा बर्फबारी हुई है, भूकंप से हुई हरकत के बाद एवलांच आने का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने भी लोगों को अलर्ट कर दिया है। पर्वतीय इलाकों का रुख न करने को लेकर आगाह किया है। पर्यटकों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है कि ऊंचाई वाले व एवलांच संभावित क्षेत्र का रुख न करें। भूकंप के बाद हुई हरकत के कारण कभी भी बर्फ के पहाड़ दरक सकते हैं।

बांग्लादेश में हाल में हिंदुओं पर हुए हमलों के पीछे बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा

कोलकाता।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पश्चिम बंगाल इकाई ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हाल में हिंदुओं पर हुए हमलों के लिए राज्य में हुई चुनाव-बाद हिंसा को जिम्मेदार ठहराया, साथ ही मुद्दे पर राज्य के बुद्धिजीवियों की चुप्पी के लिए उनकी आलोचना भी की। आरएसएस के बंगाल प्रांत प्रचारक जिष्णु बसु ने कहा कि राज्य में इस साल हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद हिन्दुओं पर हुए हमले के कारण बांग्लादेश में हिंसा को बढ़ावा मिला। बसु ने कहा, अगर आप बांग्लादेश में हिंसा का तौर तरीका देखेगा, तब समझ में आएगा कि घटना के पीछे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा प्रमुख कारण है। हिंदू बंगालियों पर हुए हमलों से संदेश गया कि कि हिंदू बंगाली हार गए हैं और इससे सीमा के उस पार भी चरमपंथियों को प्रोत्साहन मिला जिससे उन्होंने वहां हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हमले किए।

पांच नवंबर को केदारनाथ धाम की यात्रा पर जाएंगें पीएम मोदी

देहरादून ।

अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच नवंबर को केदारनाथ धाम जाकर 400 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले है। प्रधानमंत्री का दौरा शीतकाल के लिए मंदिर के कपाट बंद होने से एक दिन पहले हो रहा है। केदारनाथ के कपाट हर साल दीवाली के दो दिन बाद भैया दूज के पावन पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए जाते हैं जो अगले साल फिर अप्रैल-मई में खोले जाते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने दौरे में करीब 400 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में भव्य केदारपुरी का निर्माण हो रहा है और अपने इस दौरे में वह आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण भी करने वाले है।

आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सीएम सरमा को नोटिस

गुवाहाटी ।

चुनाव आयोग ने असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्व सरमा को राज्य में विधानसभा उपचुनाव प्रचार के दौरान सड़क एवं अन्य विकास परियोजनाओं का वादा करके आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है,अगर उक्त समय सीमा के भीतर जवाब नहीं दिया जाता है,तब आयोग आगे की कार्रवाई करेगा।''आयोग ने कहा कि उस दो शिकायतें मिलीं कि सरमा ने असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पर भवानीपुर, थावरा और मारियानी विधानसभा सीटों के लिए प्रचार के दौरान मेडिकल कॉलेज, पुल, सड़क, उच्च विद्यालय,स्टेडियम और खेल परिसर बनवाने की घोषणाएं कीं। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्होंने चाय बागान मजदूरों के स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहयोग देने की भी घोषणा की। राज्य में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होंगे और मतगणना दो नवंबर को होगी।

आसियान-भारत सम्मेलन में मोदी साझे हित एवं सुरक्षा मुद्दों पर करेंगे रचनात्मक संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को सम्मेलन में करेंगे शिरकत

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को आसियान-भारत सम्मेलन में साझे हित एवं सुरक्षा मुद्दों पर रचनात्मक संवाद करेंगे। पीएम मोदी ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोलकिया के आमंत्रण पर 18वें दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन, आसियान-भारत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में आसियान-भारत रणनीतिक साझेदारी, कोविड-19 व स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा व संपर्क सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी एक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई। आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष व सरकारों के मुखिया भाग लेंगे। यह सम्मेलन प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है जो आसियान व भारत को शीर्ष स्तर पर संवाद का मौका प्रदान करता है। पीएमओ ने कहा कि इस आयोजन से एक दिन पहले बुधवार को प्रधानमंत्री 16वें पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन में भी डिजिटल माध्यम से हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद सहित क्षेत्रीय व अंतरराष्ट्रीय हित के मुद्दों व चिंताओं पर चर्चा की जाएगी। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन भारत-प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों और क्षेत्र में एक प्रमुख विश्वास-निर्माण तंत्र पर चर्चा करने के लिए एक प्रमुख नेतृत्व-प्रधान मंच है। पूर्वी एशिया के रणनीतिक और भौगोलिक अभ्युदय में इस मंच ने अहम भमिका निभाई है। इसमें 10 आसियान देशों के सदस्यों के अलावा भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। पीएमओ ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई के सुल्तान के आमंत्रण पर डिजिटल माध्यम से होने वाले 18वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में 28 अक्टूबर को हिस्सा लेंगे।' पिछले कुछ वर्षों में भारत और आसियान देशों के बीच संबंधों में प्रगति देखी गई है। इस दौरान व्यापार और निवेश के साथ ही सुरक्षा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग को आगे ले जाने को केंद्र में रखा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल नवंबर में 17वें आसियान सम्मेलन में हिस्सा लिया था। इस बार वह नौवें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएमओ ने कहा कि आसियान-भारत साझेदारी साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सभ्यता के मजबूत आधारों पर आधारित है। आसियान समूह शुरू से भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति और हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर व्यापक दृष्टिकोण का मूल केंद्र रहा है। वर्ष 2022 आसियान-भारत संबंधों के 30 वर्षों का गवाह बनेगा। ज्ञात हो कि आसियान का उद्देश्य साझे हित एवं चिंता के राजनैतिक एवं सुरक्षा मुद्दों पर रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देना और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विश्वास बहाली एवं निरोधात्मक राजनय की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देना है।

सिर्फ खरीददार नहीं बल्कि ड्रग्स स्मगलिंग में भी शामिल है आर्यन खान- एनसीबी

नई दिल्ली (एजेंसी)।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने बॉम्बे हाईकोर्ट में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान द्वारा दायर जमानत याचिका का विरोध किया है। एनसीबी ने आरोप लगाया है कि आर्यन न केवल ड्रग्स लेता था, बल्कि वह अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में भी शामिल था। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि आर्यन खान और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी नाम की एक महिला जांच को पटरी से उतारने की कोशिश में सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ कर रही थी। दूसरी ओर, आर्यन खान के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट को एक अतिरिक्त नोट प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े और कुछ राजनीतिक हस्तियों के बीच प्रसारित किए जा रहे आरोपों और काउंटर आरोपों से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

एनसीबी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान द्वारा दायर जमानत याचिका के जवाब में अपना हलफनामा दायर किया। न्यायमूर्ति एन डब्ल्यू सांबरे की एकल पीठ द्वारा दिन में इस मामले पर सुनवाई होने की संभावना है। एनसीबी ने अपने हलफनामे में कहा कि मामले की जांच को पटरी से उतारने की गलत मंशा से चल रही जांच से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। हलफनामे में पूजा ददलानी का भी जिक्र किया गया और कहा गया, ÷ऐसा लगता है कि जब जांच चल रही है तो इस महिला ने पंच गवाहों को प्रभावित किया है। एनसीबी ने कहा कि जमानत याचिका गलत है। एजेंसी ने कोर्ट से कहा है कि मामले की अब तक की जांच में आर्यन खान की ड्रग्स की अवैध खरीद, परिवहन और उसके खपत में भूमिका का खुलासा हुआ है। एजेंसी ने कहा कि प्रथम दृष्टया जांच से पता चला है कि आर्यन खान अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट से ड्रग्स की खरीद करता था, जो इस मामले में एक आरोपी भी है।याचिका में कहा गया है, आवेदक (आर्यन खान) विदेशों में कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में था, जो ड्रग्स की अवैध खरीद के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होते हैं।÷ हलफनामे में आगे कहा गया है कि भले ही आर्यन खान के पास से ड्रग्स नहीं मिले हों, लेकिन उसने इस साजिश में भाग लिया है।

29 अक्टूबर को अदालत में हाजिर हो

मोदी सरनेम पर टिप्पणी करना राहुल गांधी को पड़ा मंहगा

सूरत (एजेंसी)।

मानहानि केस में गुजरात के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल गांधी को हाजिर होने को कहा है। सूरत की मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम पर टिप्पणी को लेकर तलब कर उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले के संबंध में बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्टूबर को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी की थी।जिसमें सूरत हाईकोर्ट में इसी मामले में सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ए एन दवे ने राहुल गांधी को अपना बयान दर्ज करने के लिए 29 अक्टूबर को पेश होने के लिए कह दिया है।इससे पहले कांग्रेस नेता आखिरी बार साल 24 जून 2021 को अदालत में पेश हुए थे। इतना ही नहीं, इससे पहले राहुल गांधी अक्टूबर 2019 में अदालत के सामने पेश होकर अपनी टिप्पणी के लिए दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था। राहुल गांधी के वकील किरीट पंवाला ने कहा कि अदालत ने मौखिक रूप से राहुल गांधी को दो नए गवाहों की गवाही पर अपना आगे का बयान दर्ज करने के लिए 29 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश दिया। राहुल गांधी के उस दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच अदालत में मौजूद रहने की संभावना है। बता दें कि सूरत के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अप्रैल 2019 में गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में भाजपा विधायक ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने 2019 में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को यह कहकर बदनाम कर दिया था कि 'सभी चोरों का सामान्य सरनेम मोदी कैसे है?' पूर्णेश मोदी अब मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली नई गुजरात सरकार में मंत्री हैं, जिनके पास सड़क और भवन, परिवहन, नागरिक उड्डयन और पर्यटन और तीर्थ विकास विभाग हैं। अदालत के समक्ष गांधी की अंतिम उपस्थिति के बाद से दो और गवाहों की गवाही ली गई- कर्नाटक में कोलार के तत्कालीन चुनाव अधिकारी जहां कांग्रेस नेता ने भाषण दिया था और एक वीडियो रिकॉर्डर जिसे चुनाव आयोग ने अपना भाषण रिकॉर्ड करने के लिए नियोजित किया था।लोकसभा चुनाव से पहले 13 अप्रैल 2019 को कोलार में रैली के दौरान अपने भाषण में तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कथित तौर पर पूछा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी ... . सभी चोरों का सामान्य सरनेम मोदी कैसे है?

आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की तीन दिवसीय बैठक 28 अक्टूबर से

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की तीन दिवसीय बैठक 28 अक्टूबर से धारवाड़ जिले में होगी जिसमें समसामयिक विषयों पर चर्चा के अलावा संगठन एवं शाखाओं के विस्तार तथा प्रशिक्षण कार्यों का लेखाजोखा होगा और आगे के कार्यों की रूपरेखा तैयार होगी। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी ने इसकी जानकारी दी। पदाधिकारी ने बताया,28 से 30 अक्टूबर तक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी परिषद की बैठक धारवाड़ जिले के राष्ट्रोत्थान विद्या केंद्र में होगी।'' उन्होंने बताया कि बैठक में सरसंघचालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सहित वरिष्ठ प्रचारक, देश भर से करीब 350 प्रचारक एवं पदाधिकारी तथा कुछ चुनिंदा अनुषंगी संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेने वाले है। उन्होंने बताया,हर वर्ष मार्च में संघ की प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है जिसमें लिये गए निर्णयों एवं तय किये गए कार्यक्रमों की छह महीने बाद अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में समीक्षा की जाती है। '' पदाधिकारी ने बताया कि कार्यकारी मंडल की बैठक में समसामयिक विषयों पर चर्चा के अलावा संगठन एवं शाखाओं के विस्तार, प्रशिक्षण कार्यों का लेखाजोखा होगा और आगे के कार्यों की रूपरेखा तैयार की जायेगी। यह पूछे जाने पर कि इस बैठक में क्या कोई प्रस्ताव पारित होगा, संघ के पदाधिकारी ने कहा, '' आमतौर पर कार्यकारी मंडल की बैठक में प्रस्ताव पारित नहीं होता है।

देश में घटा कोरोना का कहर, बीते 238 दिनों में सबसे कम आए नए केस

नई दिल्ली (एजेंसी)।

भारत में एक दिन में कोविड-19 के 12,428 नए मामले सामने आए हैं, जो पिछले 238 दिन में सामने आए सबसे कम दैनिक मामले हैं। वहीं, देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,63,816 हो गई है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या बढ़कर 3,42,02,202 हो गई है। इस दौरान संक्रमण से 356 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,55,068 हो गई। केरल ने संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करने के बाद मृतक संख्या में 228 का इजाफा किया है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण से राज्य में 53 लोगों की मौत हुई। आंकड़ों के अनुसार, देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,63,816 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.49 प्रतिशत है। यह दर मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 3,879 की कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.18 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। देश में अभी तक कुल 60,19,01,543 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 11,31,826 नमूनों की जांच सोमवार को की गई। देश में दैनिक संक्रमण दर 1.10 प्रतिशत और साप्ताहिक संक्रमण दर 1.24 प्रतिशत है। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी।

1.36 करोड़ की ठगी मामले में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा को मिली राहत

लखनऊ (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोसिस वेलनेस सेंटर कंपनी की फ्रेंचाइजी में ठगी के मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनकी मां सुनंदा को बड़ी राहत मिली है। लखनऊ पुलिस ने जांच के बाद इस मामले से शिल्पा शेट्टी और उनकी मां का नाम हटा दिया है। बता दें कि गोमती नगर निवासी ज्योत्सना सिंह ने विभूति खंड थाने में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनकी मां सुनंदा, शिल्पा की मैनेजर किरण बावा समेत कई लोगों पर 1.36 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक आयोसिस वेलनेस सेंटर कंपनी की फेंचाइजी देने के नाम पर ज्योत्सना के साथ यह ठगी की गई थी। ज्योत्सना ने आरोप लगाया था कि शिल्पा की मैनेजर किरण बावा ने अपने साथ शिल्पा के कई वीडियो दिखाकर झांसे में लेकर उन्हें कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलवा दी थी। ज्योत्सना के मुताबिक उन्होनें विभूति खंड में किराए की दुकान लेकर, साज सज्जा पर काफी खर्च कर सेंटर की शुरुआत भी कर दी थी। आरोप है कि कंपनी ने वादा किया था कि वेलनेस सेंटर का उद्घाटन खुद शिल्पा शेट्टी करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि शिल्पा को बुलाने के लिए उनसे 11 लाख रुपए मांगे गए थे। एफआईआर के मुताबिक कुछ समय बाद किरण बावा ने सेंटर पर कब्जा कर लिया था जबकि उनका 1.36 करोड़ रुपया सेंटर पर खर्च हो चुका था जो उन्होंने अपना मकान गिरवी रख कर लिया था। एफआईआर दर्ज होने के बाद 11 अगस्त को विभूति खंड पुलिस ने मुंबई जाकर शिल्पा शेट्टी और किरण बाबा को नोटिस दिया था।

लखीमपुर हिंसा केस में गवाहों के बयान को लेकर असमंजस

सुनवाई 8 नवंबर तक टली

नई दिल्ली (एजेंसी) ।

यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में देश की सर्वोच्च अदालत में एक बार फिर सुनवाई हुई। इस बार फिर से गवाहों के बयान दर्ज से संबंधित मामले में असमंजस दिखा। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यूपी सरकार की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे से पूछा, 'घटना के वक्त सैकड़ों लोग थे। उनमें सिर्फ 23 ही चश्मदीद हैं?' दरअसल, यूपी के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट में कहा, '30 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने हो चुके हैं। उनमें 23 प्रत्यक्षदर्शी हैं।' साल्वे ने आगे बताया कि हमने गवाही के लिए विज्ञापन जारी भी किया। वीडियो सबूत भी मिले हैं। जांच जारी है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में हुई हिंसक घटना में चार किसानों और एक पत्रकार सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। अदालत ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है और पिछली सुनवाइयों में जांच में असंतोषजनक एक्शन के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई भी की। इस मामले में केंद्रीय मंत्री का बेटा भी मुख्य आरोपियों में शामिल है। अदालत ने सुनवाई के दौरान साफ पूछा कि वहां 4-5 हजार लोग थे। सब स्थानीय थे क्या? इसपर वकील साल्वे ने हां बोलते कहा कि बस कुछ ही लोग दूसरे राज्य के थे। कोर्ट ने कहा कि वह लोग जांच को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं। फिर उनकी पहचान में क्या दिक्कत हो रही है? शीर्ष अदालत ने कहा, 'गंभीर गवाहों की पहचान जरूरी है। वीडियो का परीक्षण जल्दी करवाइए, नहीं तो हमें लैब को निर्देश देना होगा।' वहीं, गवाहों की सुरक्षा की भी बात कही गई। इसके अलावा इस बार अदालत ने कहा कि राज्य की तरफ से दाखिल हुई रिपोर्ट में जांच में प्रगति होती दिखी है। हम गवाहों की सुरक्षा का निर्देश देते हैं और सभी के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करवाए जाएं। उधर सुनवाई के दौरान घटना में मारे गए श्याम सुंदर की पत्नी रूबी देवी और पत्रकार रमन कश्यप के परिवार ने जांच सही से न होने की शिकायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसपर यूपी सरकार से रिपोर्ट देने को कहा है। अगली सुनवाई 8 नवंबर के लिए टाल दी गई। पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस की खिंचाई करते हुए जांच की धीमी रफ्तार और मंशा पर सवाल उठाए।

सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अभियुक्तों की पुलिस और न्यायिक हिरासत की स्थिति तथा गवाहों व पीड़ितों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया पर सवालों में घेरते हुए कहा, 'हमें लगता है कि आप देरी करने के लिए धीमी गति अख्तियार किए हैं। कृपया इस धारणा को दूर करें।'

वहीं, पिछली बार यूपी सरकार की ओर से पेश वकील से वार्तालाप करते हुए इस हिंसा के संबंध में दो मामले गिनाए थे। एक किसानों को गाड़ी से रौंदने का है और दूसरा तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या का है, जिसमें जांच थोड़ी मुश्किल है क्योंकि भीड़ से अभियुक्तों की शिनाख्त करानी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दोनों मामलों को अलग कर देंगे। यहां सिर्फ किसानों को गाड़ी से रौंदने पर सुनवाई हो रही है।

पिछले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट को लेकर नाराजगी भी जताई। अदालत ने कहा, 'राज्य सरकार द्वारा अंतिम क्षणों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई।'

कार्यालय ऑफिस
क्रांति समय दैनिक समाचार में प्रेसनोट,नोटिस,वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-krantisamay@gmail.com

समस्या आपकी हमें भेजे
अपने क्षेत्र में समस्याएं हमें लिखे या बताएँ और समस्याएं का हल संबंधित विभाग से मिलेगा
मोबाईल:-987914180
या फोटा,वीडियो हमें भेजे

कार्यालय ऑफिस
क्रांति समय दैनिक समाचार
भारत के अन्य राज्यों में जिला ब्यूरों और अन्य शहर,ग्राम में पत्रकारों की नियुक्त के लिए आवेदन कर सकते है
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-9879141480
ईमेल:-krantisamay@gmail.com